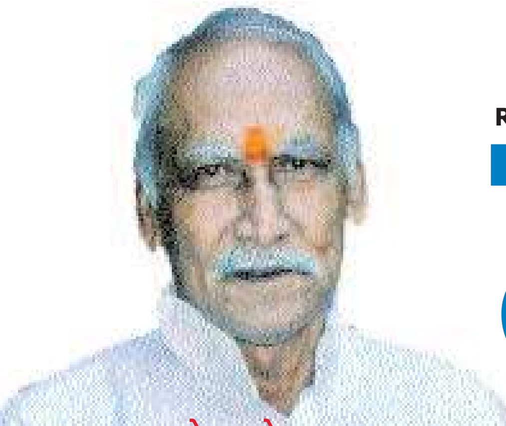
प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ.. सच

Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-03, अंक-42 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरुवार 22 जुलाई 2021 | पृष्ठ-8, मूल्य-5 रुपए

सुविचार

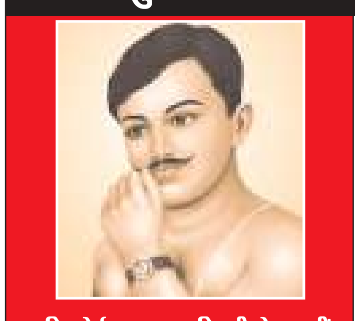
यदि कोईयुवा मातृभूमि की सेवा नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ है..

◂◂ चन्द्रशेखर आजाद

भारत-पाक बॉर्डर पर एक दूसरे भेंट की मिठाईयां

नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पाकिस्तान रेंजर्स ने सीमा के विभिन्न स्थलों पर ईद-उल-अजहा (बकरीद) के अवसर पर एक दूसरे को मिठाइयां भेंट की। वर्ष 2019 के बाद पहली बार दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने आपस में मिठाइयां बांटकर इस त्योहार की खुशियां साझा की हैं। उल्लेखनीय है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान ने एकतरफा तरीके से त्योहारों के अवसरों पर मिठाइयों के आदान-प्रदान करने के चलन को रोक दिया था।

बीएसएफके प्रवक्ता ने बताया कि, बीएसएफऔर पाकिस्तान रेंजर्स के बीच ईद के मौके पर मिठाइयों का आदान-प्रदान पंजाब के अमृतसर जिले में अटारी स्थित संयुक्त सीमा चौकी पर हुआ। यह चौकी पाकिस्तान के वाघा सीमा के सामने पड़ती है। अधिकारियों ने बताया कि, इसी तरह मिठाइयों का आदान-प्रदान दोनों देशों के बलों के बीच राजस्थान में पाकिस्तान से लगती सीमा पर भी हुआ। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाने के बाद पहली बार दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच मिठाइयों का आदान-प्रदान हुआ है।

सीएए और एनआरसी पर आरएसएस प्रमुख ने दिलाया भरोसा

गुवाहाटी, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर देश के मुसलमानों को भरोसा देते हुए कहा है कि, उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा है कि, अल्पसंख्यकों को लेकर विभाजन के समय जो वादा किया गया था, भारत उसका पालन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। भागवत ने कहा कि, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या लोकतंत्र भारत को दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं है। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा, सीएए किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। विभाजन के बाद एक आश्वासन दिया गया कि, हम अपने देश के अल्पसंख्यकों की चिंता करेंगे। हम आजतक उसका पालन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान नहीं कर रहा है।

ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र के जवाब के विरोध में विपक्ष विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में

नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में केन्द्र सरकार के जवाब पर सियासत गर्मा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जवाब से विपक्ष भड़क गया है और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल राज्यसभा में यह सवाल पूछा गया था कि, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई है। इसके जवाब में कहा गया था कि, राज्यों ने केन्द्र सरकार ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया है।

इस मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इस संकट काल में सरकार ने देश को अनाथ छोड़ दिया था। सरकार को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करेगी।

प्रियंका गांधी ने भी दी तीखी प्रतिक्रिया- प्रियंका गांधी ने केन्द्र सरकार को घेरते हुए अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से इसलिए मौतें हुई क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था। सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता भी नहीं दिखाई।

जल्द आएगी बच्चों के लिए वैक्सीन

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बचाव के चलते देश में वयस्कों का वैक्सीनेशन कहीं हद तक कवर कर लिया गया है, जिस वजह से दूसरी लहर में भी राहत देखने को मिली। लेकिन अब तीसरी लहर का खतरा सीधे तौर पर बच्चों पर मंडरा रहा है। देश में तमाम बच्चों के अभिभावक कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंतित नजर आ रहे है। ऐसे में एक अच्छी खबर यह है कि, बहुत ही जल्द बच्चों की भी वैक्सीन आने वाली है।

एम्स के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने बताया कि, जहां एक तरफ कम संक्रमण वाले जिले में स्कूल खोले जाने की बात कही है। वहीं उनका कहना है कि, बच्चों का वैक्सीनेशन होने से माता-पिता का उनकी सुरक्षा को लेकर कॉन्फिडेंस बेहतर होगा।

बच्चों के लिए ज्यादा विकल्प मौजूद- डॉ. गुलेरिया ने बताया कि, बच्चों पर टीकाकरण के लिए को-वैक्सीन के अलावा भी कई और विकल्प हैं जिसमें जाइडस का जायकोव-डी वैक्सीन है। इस वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर भी हुआ है। कंपनी ने भारत में इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी है। इसके अलावा फाइजर का भी ट्रायल बच्चों पर हुआ है, जिसे एफडीए ने बच्चों में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में कई विकल्प होगें, जिस तरह के सबूत आ रहे हैं उससे यह भी देखा जा रहा है कि, बच्चों में वायरस के खिलाफएंटीबॉडी भी मिल रही है।

न्यूज ब्रीफ

राज्यों को महामारी से मुकाबले के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए- मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस प्रबंधन पर सर्वदलीय बैठक में केंद्र और राज्यों को एक टीम के रूप में मिलकर काम करने और महामारी से निपटने के लिए राजनीति से ऊपर उठने का आह्वान किया। इस बैठक में कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने हिस्सा नहीं लिया। सूत्रों ने बताया कि, केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में मोदी ने कहा कि, भारत बीमारी से प्रभावित आबादी के अनुपात में कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। लेकिन ब्रिटेन जैसे कुछ देशों में संक्रमण के बढ़ते मामलों को रेखांकित करते हुए उन्होंने सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि, कुछ और कंपनियों के वैक्सीन आगामी दिनों में उपलब्ध होने की संभावना है और सरकार द्वारा वैक्सीनेशन पर दिए जा रहे जोर के बारे में बताया। करीब तीन घंटे तक चली बैठक में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना प्रबंधन पर एक प्रस्तुति दी। इसके बाद विभिन्न दलों के नेताओं ने कुछ सवाल पूछे और सुझाव दिए। शिवसेना और टीएमसी ने क्रमशः महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लिए और वैक्सीन की मांग की। बीजद, टीएमसी और कुछ अन्य दलों ने भी सरकार से स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सिन के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की। टीआरएस नेता नामा नागेश्वर राव ने सरकार से वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ावा देने का आग्रह किया और चिंता जताते हुए कहा कि महामारी की दूसरी लहर ने ग्रामीण आबादी को भी प्रभावित किया है।

मैंने अपने फोन का कैमरा ढक लिया है- ममता बेनर्जी

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बेनर्जी ने पेगासस फोन हैकिंग विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता बेनर्जी ने कहा कि, उन्होंने अपने फोन के कैमरे को कवर कर लिया है, ताकि उसकी हैकिंग के जरिए उनकी जासूसी न की जा सके। ममता बेनर्जी ने कहा, हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं, पेगासस डराने वाला है, मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती। आप जासूसी के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। मैंने इससे बचने के लिए अपने फोन को प्लास्टर कर लिया है। इसी तरह से हमें केंद्र सरकार को भी ढक देना है, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। ममता बेनर्जी ने अपने फोन के बैकसाइड में लगी टेप को दिखाते हुए कहा, मैं शरद पवार जी, पी. चिदंबरम, दिल्ली के सीएम या ओडिशा के मुख्यमंत्री को कॉल नहीं कर सकती हूं, मेरा फोन टैप किया जा रहा है। देखिए कैसे मैंने अपने फोन के कैमरा पर टेप लगा लिया है। ममता बेनर्जी ने कहा कि, विधानसभा चुनाव से पहले मैं अपने पार्टी नेताओं से मिल रही थी और उस समय मेरा फोन भी साथ में था। उन्होंने हर चीज को रिकॉर्ड कर लिया।

मंडी अधिकारियों की व्यापारी से मिलीभगत, सचिव की आईडी हैक कर पहुंचाया राजस्व को नुकसान

माही की गूंज, झाबुआ/थांदला। धर्मेंद्र पंचाल

सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के कई किस्से आपने सुने होंगे। लेकिन थांदला कृषि उपज मंडी में 13 जुलाई 2021 से अधिकारियों को एक नई बात पता चली है कि, बिना मंडी अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यापारी द्वारा ई-अनुज्ञा को सत्यापित किया जा रहा है। आपको बता दे कि, म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2018 से अनाज परिवहन के लिए बनाई जाने वाली अनुज्ञा अब ऑनलाइन व्यापारी द्वारा बनाए जाने के नियम लागू किए है। परंतु व्यापारी द्वारा बनाई गई ई-अनुज्ञा का सत्यापन मंडी के अधिकारी व कर्मचारी करते है। जिसके लिए विभाग द्वारा अधिकारियों को आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। मंडी अधिकारियों का कहना है कि, सत्यापन के लिए उपयोगी आईडी और पासवर्ड को थांदला के शिवानी इंटरप्राइजेस के मालिक ने हैक कर अनुज्ञा सत्यापन करने हेतु दुरूपयोग किया और मंडी राजस्व को नुकसान पहुंचाया है।

मंडी सचिव अश्विन वसावा ने बताया कि, व्यापारी द्वारा आईडी पासवर्ड को हैक कर लिया है और उसके द्वारा अनुज्ञा को सत्यापित करने का प्रमाण मिला है। जिसके बाद थांदला पुलिस थाना, साइबर सेल झाबुआ सहित वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में अवगत करवाया गया है। जांच दल व स्थानीय अधिकारियों ने 18 जुलाई 4.40 बजे, शिवानी इंटरप्राइजेस के पुराने मंडी स्थित गोदाम को भी सील कर दिया है। जिस पर लिखा गया है कि, शिवानी इंटरप्राइजेस के मालिक सुनील राठौर थांदला द्वारा इनको दिए गए मंडी लायसेंस के नियमों व शर्तों का उल्लंघन कर साइबर अपराध करने से मंडी अधिनियम की धारा 19/20/23/ व उपविधि 19 के प्रावधानों के तहत गोडाउन को प्रकरण का निराकरण करने तक सील किया गया है। यह कार्रवाई फर्म के प्रतिनिधियों के समक्ष हुई है। मंडी सचिव वसावा का कहना है कि, मैं कोविड के चलते दो माह से अवकाश पर था, जब आया तो मामला संज्ञान में मिला। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाकर पुलिस थाने व साइबर सेल में आवेदन दिया है।

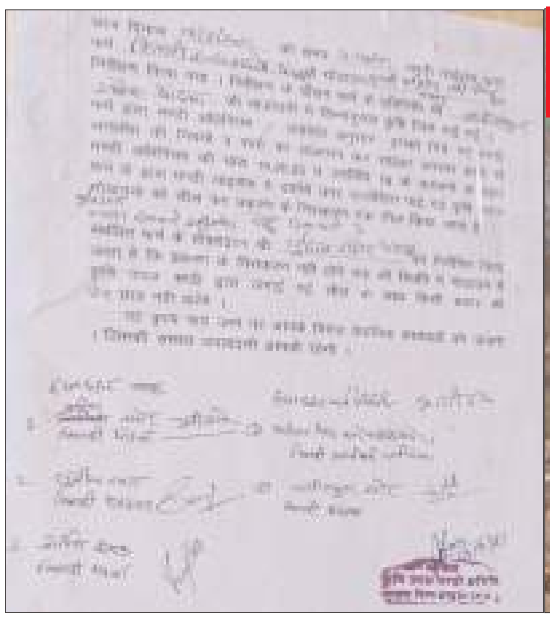

मामला: थांदला मंडी सचिव की आईडी हैक कर व्यापारी कर रहा था अनुज्ञा सत्यापित

जांच के लिए टीम गठित

मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय उपसंचालक द्वारा झाबुआ व पेटलावद मंडी सचिव सहित 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। जो थांदला मंडी पहुंच कर आवश्यक दस्तावेज का संग्रहण कर अपने साथ ले गए है और इंदौर स्थित वरिष्ठ कार्यालय को सौंपे जाएंगे।

जांच के नाम पर मीडिया को दस्तावेज तक नहीं दे रहे अधिकारी

पूरे मामले को लेकर जब थांदला की मीडिया ने छानबीन की तो अधिकारी खुद को व व्यापारी को बचाते नजर आए। उनके द्वारा किसी भी तरह के दस्तावेज मीडिया को जांच के नाम पर उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे है। तब मौके पर मौजूद मीडियाकर्मियों ने लिखित में मंडी सचिव को दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन दिया। आवेदन लेने के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मीडिया से दस्तावेज छुपाए जा रहे है। जो विचारनीय है...वहीं भारसाधक अधिकारी व एसडीएम ज्योति परस्ते का कहना है कि, हमको भी आपके द्वारा जानकारी मिली है, विभागीय जांच चल रही है। जांच के बाद ही आपको कुछ बता पाएंगे।

क्या व्यापारी हैकर है...?

एक आम नागरिक और पाठक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको लगता है कि, थांदला जैसे क्षेत्र में रहने वाला व्यापारी हैकर हो सकता है...? सूत्रों का कहना है कि, मंडी के कई कर्मचारियों को नई तकनीक से अनुज्ञा का सत्यापन कार्य नहीं आता है। ऐसे में व्यापारी को किसी कर्मचारी द्वारा आईडी पासवर्ड दिया गया होगा। या यह भी हो सकता है कि, याद न रहने की स्थिति में कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा कोई कागज पर इस तरह की गोपनीय चीजें लिखी गई हो और वह व्यापारी को मिली गई हो। जिसके बाद यह पूरा खेल शुरू हुआ हो...?

इसलिए होता है यह खेल

मंडी की ई-अनुज्ञा जारी करने के बाद व्यापारी 4 घंटे में उसे डिलीट भी कर सकता है, इसका दुरूपयोग जबरदस्त तरीके से हो रहा है।

एक व्यापारी का कहना है कि, चूंकि यदि गाड़ी म.प्र. से म.प्र. में जा रही है तो यह ई-अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत करने पर राशि वापस व्यापारी को मिल जाती है। परंतु जब गाड़ी गुजरात या अन्य राज्यों में जाती है तो ई-अनुज्ञा की यह राशि व्यापारी को नहीं मिलती। बस इसी राशि को बचाने के लिए व्यापारी ई-अनुज्ञा पत्र को जारी तो जरूर करता है, परंतु म.प्र. की सीमा पार करते ही उसे 4 घंटे के भीतर ही डिलीट कर देता है। मतलब साफ है गुजरात व राजस्थान के समीपस्थ होने के चलते थांदला में यह खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है।

मंडी चैकपोस्ट खत्म होने से व्यापारी हुए बेलगाम

समीपस्थ राज्यों में प्रवेश से पहले मंडी चैक पोस्ट राजस्व बढ़ाने में काफी मदद करती थी। जहां पर अनुज्ञा की एक प्रति जमा करवाना जरूरी होता था। तो वहीं मंडी निरीक्षकों द्वारा गाड़ी की जांच भी की जाती थी। परंतु अब इन चैक पोस्ट को खत्म कर दिया है, तो व्यापारी बेलगाम हो गए है। म.प्र. की सीमा तक 4 घंटे के भीतर तक जारी ई-अनुज्ञा से काम चल जाता है। तो वहीं गाड़ी के सीमा से बाहर होते ही व्यापारी अनुज्ञा को डिलीट कर देते है। मतलब सरकारी राजस्व का सीधा-सीधा नुकसान होता है।

विस्तृत जांच में कई और व्यापारी आएंगे जद में

सूत्रों का कहना है कि, इस तरह का काम केवल एक व्यापारी द्वारा नहीं किया गया होगा। यह तो व्यापारी और अधिकारी की मिलीभगत में कोई कमी के चलते बाहर आया है। यदि विस्तृत जांच होगी तो कई और व्यापारी भी इस तरह के खेल में शामिल हो सकते है। चूंकि थांदला के अधिकांश व्यापारी गुजरात माल ढोकर भेजते है, तो राजस्व को बचाने के चक्कर में इस तरह के खेल में कई और शामिल होंगे ये तय है।

व्यापारी बचने के लिए ले रहा राजनेताओं की शरण

पूरे मामले में व्यापारी के फंसने के चलते बचाव के लिए सत्तारूढ़ दल के बड़े प्रतिनिधियों व नेताओं की शरण ली जा रही है। मंगलवार को भी एक बड़े नेता की शरण में जाकर बचाव के रास्ते खोजे गए। तो वहीं अधिकारी इस पूरे मामले में अपने आपको बेकसूर बताकर पूरा रायता व्यापारी पर डालना चाह रहे है। देखना होगा कि, पूरे मामले में व्यापारी साम-दाम-दंड-भेद का उपयोग कर अपने ऊपर होने वाली कार्रवाई को रूकवा पाएगा या अधिकारी इस मामले में खुद को बचा पाएंगे। क्योंकि सरकार की गोपनीय चीजों का उपयोग, व्यापारी द्वारा बिना सेटिंग या मिलीभगत के अकेला कर पाना नामुमकिन ही लगता है।

गूंज सवाल

◂◂ व्यापारी को मंडी सचिव की आईडी मिली कैसे?

◂◂ व्यापारी हैकर नहीं है, तो फिर देने वाले कर्मचारी पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं?

◂◂ क्या व्यापारी का एक गोदाम सील करने से उसका व्यापार बंद हो जाएगा?

◂◂ मंडी अधिकारियों ने पूरे मामले को भारसाधक अधिकारी को तत्काल क्यों नहीं बताया?

◂◂ पूरे मामले से मीडिया को दूर क्यों रखा गया?

कृषि उपज मंडी थांदला।

जांच करते दस्तावेज संग्रहण करते अधिकारी।

पुरानी मंडी स्थित गोदाम को सील करते जांच दल व मंडी टीम के सदस्य।

प्रभारी मंत्री के दौरे के बाद बड़ी राजनीतिक हलचल

ट्रांसफर के लिए भाजपा नेताओं के पास लगी लाइन, आखिर बामनिया में मंत्री जी का क्यों नहीं हुआ स्वागत !

माही की गूंज, पेटलावद।

जिले के प्रभारी मंत्री नियुक्त होने के बाद पहली बार जिले के प्रवास पर आए स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन विभाग राज्य मंत्री इंदरसिंह परमार के दौरे के बाद भाजपा नेताओं में अचानक सक्रियता आ गई और ये सक्रियता पार्टी के लिए नही बल्कि सरकार द्वारा कुछ समय के लिए ट्रांसफर हेतु खोली गई लाइन के लिए है। मंत्री जी के दौरे के बाद उनके साथ सेल्फी वाले नेता मंत्री जी से संबधो का हवाला देकर ट्रांसफर चाहने वालो का खूब शोषण कर रहे हैं। जबकि सरकार ने ट्रांसफर का प्रतिशत आने और जाने का तय कर रखा है, जिसके अनुसार पार्टी नेताओं द्वारा मनचाहे अनुसार ट्रांसफर नही होगा और जिसको ट्रांसफर करवांना है वो इसकी बोली अधिक से अधिक लगाकर अपना काम करवा सकता है। ये ही आलम है कि, भाजपा के टटपुँजिए नेता भी बड़े से बड़े अधिकारी के ट्रांसफर के दावे भर रहे हैं जिनसे जनपद और शिक्षा विभाग में ट्रांसफर हुए कर्मचारी रिलीव नही हुए। अब देखना है कि, ट्रांसफर के इस खेल में कितने लोग जा पाते और कितने आ पाते हैं। लेकिन ये तय है कि, इस खेल के बाद कई पीड़ितों की कहानी सामने आएगी, जिसमे कहा जाएगा आपका पेमेंट ऊपर से ही नही आया है।

डरे-डरे से जिलाध्यक्ष, बामनिया में नही हुआ मंत्री जी का स्वागत

भाजपा का गढ़ माने जाने वाले ग्राम पंचायत बामनिया में प्रभारी मंत्री का स्वागत नही किया गया, यहां दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन में मंत्री जी पेटलावद से बामनिया होकर निकले, जहाँ नगर प्रवेश में मण्डल अध्यक्ष और नगर के बहार होते ही जिला मंत्री व ग्राम पंचायत सरपंच (प्रधान) का आवास है, लेकिन दोनों स्थान सहित अन्य किसी भी स्थान पर मंत्री जी का स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नही किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक ऐसा नही चाहते थे कि, मंत्री जी का काफिला बामनिया में रुके क्योंकि उन्हें डर था कि बामनिया की जिस महिला ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगा रखे हैं वो कहीं मंत्री जी के पास नहीं पहुँच जाए। बस इसीलिए मंत्री जी का काफिला बिना किसी रूकावट के बामनिया से गुजर गया और बामनिया सहित पेटलावद मण्डल की नाक कट गई।

भला हो नेताओ का, प्रभारी मंत्री ने की महामंत्री से मुलाकात

जिले में जमीन तलाश रहे कुछ नेता अपने आपको बड़ा दिखाने और बताने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। संगठन के विशेष आग्रह पर दौरे में परिवर्तन कर गंगाखेड़ी होकर मंत्री जी निकले लेकिन इस यात्रा को कुछ नेताओं ने प्रभारी मंत्री को अपने यहां मुलाकात करने पहुँचे बताया। मतलब मंत्री जी पर ऊपर से दबाव पड़ा और वो सब कुछ छोड़कर महामंत्री से मुलाकात करने गंगाखेड़ी पहुँचे। वो तो भला हो नेताओ का जिन्होंने ने मंत्री जी की उम्र का लिहाज रखा वरना ये भी कहने ने नही चूकते की मंत्री जी ने फ्लाने नेता से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया।

सांसद रहे नदारद, खास लोग घूमते रहे मंत्री जी के इर्द-गिर्द

जिलाध्यक्ष और सांसद के चल रही रस्सा-कस्सी जग जाहिर है। ऐसे में दोनो मंत्री जी के इर्द-गिर्द धूमते रहे लेकिन मंत्री जी के दौरे के दूसरे दिन सांसद को आवश्यक कार्य से बहार जाना पड़ा तो जिलाध्यक्ष अपने सारे दौरे मंत्री जी के साथ वाले निरस्त कर सर्किट हाउस पर सुबह पहुँचकर मंत्री जी को अपने कार्य की जानकारी देकर निकल गए। मिली जानकारी अनुसार सांसद के कुछ खासमखास नेता जो झाबुआ जाते ही उनके देवरे धोक लगाते थे मंत्री जी के दौरे के कारण झाबुआ पहुँचे, लेकिन साहब के यहां हाजरी नही लगाई ओर साहब के विरोधियों के साथ मिलकर मंत्री जी के इर्द-गिर्द घूमते रहे। चर्चाओं में ये भी रहा है कि, नेताओं को बीच में साहब ने उन अहसान फरोश नेताओ को ''शाल में लपेट कर चांदी का जूता मारा''। बीच दौरे में यू सांसद का चले जाना भी चर्चा का विषय बना रहा।

और अंत मे...

मंत्री जी ताबड़तोड़ एक के बाद एक बैठक ओर मुलाकात के बाद मंत्री जी की हालत खस्ता हो गई, स्थिति ये बन गई कि, मंत्री जी यहां से निकलकर अपने गृह ग्राम प्रस्थान करना चाहते थे। दौरे के पहले दिन मंत्री जी को नेताओ ने रात की तीन बजे तक सोने नही दिया और रात भर खुद जागते रहे कि कोई उनसे मुलाकात करके जिले की वर्तमान स्थितियों से अवगत नही करा दे। खेर मंत्री जी पहले दौरे में पीछे बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं और आगे निकट भविष्य में उनका जिले का दौरा जल्द होने की संभावना कम ही है।

खाली कुर्सियों और गिने-चुने लोगों के साथ हुई शांति समिति की बैठक सम्पन्न

माही की गूंज, बामनिया

एक समय था जब शांति समिति की बैठक होती थी तो जनप्रतिनिधि, पक्ष, विपक्ष के नेता सहित नगर के गण्यमान्य नागरिक उपस्थित होते थे, लेकिन अब पुलिस के प्रति आम जनता के टूटते विश्वास के कारण पुलिस से दूरी बना ली है। मंगलवार को बामनिया पुलिस चौकी पर संपन्न हुई शांति समिति की बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर की गई चर्चा होना थी, जिसके लिए शोसल मीडिया सहित अन्य व्यवस्थाओ से लोगो को आमंत्रित किया गया। लेकिन चौकी परिसर में पहुँचे लोगो की संख्या पुलिस स्टाफसे भी कम थी। ऐसा केवल बामनिया चौकी ही नही कई चौकी थानों में बैठक का ये ही हाल रहा है। बामनिया चौकी में पुलिस को खाली कुर्सियों और गिने-चुने चार-छः लोगो के साथ बैठक करनी पड़ी।

सट्टा ओर अवैध शराब के व्यवसाय पर कोई रोक नही

नगर में पुलिस व्यवस्था का आलम ये है कि, नगर की गली-गुच्चो में सट्टे ओर अवैध शराब का धंधा फलफूल रहा है। पुलिस चौकी की आखों के सामने शराब ठेकेदार द्वारा दिन-रात दुपहिया और चार पहिया वाहन से अवैध शराब की सप्लाई कर रहा है, लेकिन पुलिस अपनी मासिक बंदी के कारण मौन धारण किए हुए है। ग्राम की यातायात व्यवस्था भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ी हुई है, पुलिस द्वारा की जा रही अनदेखी के कारण अपराध और विवाद बढ़ रहे हैं। जिस कारण शांति समिति की बैठक में पुलिस के प्रति विश्वास कम हुआ है।

भगवान शिव का श्रावण माह में पूजा करने से मिलता है आशीर्वाद

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

24 जुलाई पूर्णिमा के बाद 25 जुलाई से श्रावण महीने की शुरुआत हो रही है, इस बार सावन में चार सोमवार होंगे, सावन का महीना इस बार 29 दिनों का है। ज्योतिष पंडित प्रफुल्ल शुक्ला पेटलावद एवं पंडित सुधीर भट्ट सारंगी के अनुसार धार्मिक तौर पर सावन को बहुत ही पवित्र महीनों में गिना जाता है। भक्त लोग इस महीने के सोमवार को बहुत ही सौभाग्यशाली और पूर्ण फलदाई मानते हैं, सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि, सावन के सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर की विशेष कृपा होती है, कुंवारी कन्या सावन के सोमवार का व्रत करती है।

सावन महीने में भगवान भोले के भक्त सावन के सोमवार को भोले शंकर की विशेष पूजा करते हैं इस दिन भगवान भोले शंकर के भक्त उनका रुद्राभिषेक भी करते हैं। सावन में कृष्ण पक्ष की द्वितीया और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का विशेष महत्व है। हालांकि कृष्ण पक्ष पूरे 15 दिन का होगा और शुक्ल पक्ष 14 दिन का ही रहेगा। सावन में प्रदोष व्रत 5 और 20 अगस्त को होगा। उन्होंने श्रावण माह के चार सोमवार के बारे में भी बताते हुए कहा, किस सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई, दूसरा सोमवार 2 अगस्त, तीसरा सोमवार 9 अगस्त तथा चौथा सोमवार 16 अगस्त को रहेगा।

माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था यह कार्य

भगवान शिव को माता पार्वती ने पति के रूप में पाने के लिए पूरे सावन महीने में कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की और अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को सावन का यह महीना अत्यंत प्रिय है। ये ही कारण है कि, इस महीने कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती है। यह भी मान्यता है कि, सावन के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था इसलिए इस माह में अभिषेक का महत्व बताया गया है। सावन महीने में किसी भी सोमवार को पानी में दूध व काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से बीमारियां दूर होती है, साथ ही सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करने से आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होती है।

कोदली पंचायत मामले में अधिकारियों ने कर दिया निराकरण

शिकायतकर्ता ने दोबारा की शिकायत, सत्ता पक्ष के दबाव में काम करे रहे अधिकारी

माही की गूंज, पेटलावद।

ग्राम पंचायत कोदली में आंगनवाड़ी भवन निर्माण मामले में हुए घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार मामले में अधिकारी, शिकायत और मीडिया में खबरे प्रकाशित होने के बाद जांच करने पहुँचे थे और जांच दल लीपापोती कर वापस आ गया और बिना शिकायतकर्ता को संतुष्ट किए सीएम हेल्पलाइन पर निराकरण डाल दिया। शिकायतकर्ता गौरसिंह कटारा ने बताया कि, सीएम हेल्पलाइन द्वारा मैरी शिकायत का बिना जानकारी निराकरण कर दिया गया, जिसके बाद मेरे द्वारा दोबारा शिकायत दर्ज करवाई गई है। जांच पर आए अधिकारीयों ने मामला पंचायत के पक्ष में रफा-दफा कर दिया।

सत्ता के दबाव में हो रही जांच- भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाली भाजपा के नेता खुद भ्रष्टाचार में डूब गई है। ग्राम पंचायत कोदली के सरपंच कर्माबाई कटारा के पति विनेश कटारा भाजपा के पेटलावद मंडल में उपाध्यक्ष है, जिस कारण जिम्मेदारो ने मामले में लीपापोती कर दी। बताया जा रहा है, भाजपा नेताओं ने अधिकारियों पर कार्रवाई नही करने का दबाव बनाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि, ग्राम पंचायत कोदली में भ्रष्टाचार का ये कोई एक मामला नही है, यदि पूरे सात वर्षों के रिकॉर्ड और भुगतान की जांच की जाए तो लाखों के गबन का मामला उजागर होगा। ज्ञात हो कि, मामले में सीईओ नानसिंह चौहान की शिकायतकर्ता को झूठी शिकायत पाए जाने पर कार्रवाई करने की धमकी का ऑडियो भी वाइरल हो चुका है। जिसमे सीईओ साफ-साफ पंचायत की दलाली करते सुनाई दिए थे।

गरीबों का सपना, घर हो अपना, आखिर कब पूरा यह होगा सपना

माही की गूंज, थांदला। मुकेश भट्ट

प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर गरीब को यह आशा जगा दी थी कि, अपना भी एक घर होगा, परन्तु प्रक्रिया की कछुआ गति की चाल से थांदला नगर में यह योजना 85 प्रतिशत गरीबो के लिए एक सपना बनकर रह गई है। थांदला नगर क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 1 हजार 5 सौ परिवार पंजीकृत है जिसमे 230 परिवार पीएम आवास योजना से लाभान्वित हुए व 550 परिवार प्रतीक्षा सूची में है।

230 लोगो को मिला लाभ

डेढ़ हजार परिवारों के पंजीयन में मात्र 230 परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ अभी तक मिल पाया है, जिन्होंने किस्तों में राशि प्राप्त कर अपने घर का सपना पूरा कर लिया। हालांकि इस योजना में अपात्र लोग भी शामिल होकर लाभ उठाने में सफल हो गए है तो पात्र व्यक्ति अभी पीछे रहकर लाभ प्राप्त करने की सूची में शामिल है।

550 की सूची अटकी हुई है

नगर पंचायत से 550 आवासहीन व्यक्तियों की सूची प्रक्रिया अनुसार भेजी जा चुकी है जिनकी स्वीकृति अभी नही हुई है। योजना का लाभ मिलने के लिए यह आवासहीन नगर पंचायत की सम्बंधित शाखा में चक्कर लगा रहे है। पंजीयन के पश्चात इन आवासहीनों को आश्वासन दिया गया था कि, आपके नामो की सूची ऊपर भेजी गई है जो जल्द ही स्वीकृत होकर आ जाएगी और राशि आपके खाते में जमा हो जाएगी आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कर दो।

बारिश में पड़े खुले मकान

प्रतीक्षारत सूची में दर्ज नाम व शीघ्र राशि मिलने के आश्वासन पर अधिकांश लोगों द्वारा अपने मकान का कार्य वर्षात्रृतु के पहले कर लेने के उदेश्य से अपने कच्चे मकानों को खोल कर सिर पर कर्ज अथवा थोड़ी बहुत जमा पूंजी लगाकर काम चालू कर लिया। नतीजतन लंबित प्रकरण के चलते किसी भी आवासहीन की किश्त की राशि जमा नही होने से वर्षा प्रारम्भ हो जाने के बाद दुविधा की स्थिति निर्मित हो गई। कोई पुराने पत्तरे, चद्दर से तो कोई बरसाती ढंककर तो कोई ब्याज पर पैसा लेकर आवश्यक कार्य कर अपनी छत की मरम्मत करवाकर रहने को मजबूर है। जिम्मेदारों का कहना है कि, लॉकडाउन के चलते प्रक्रिया लंबित हो रही है परन्तु लॉकडाउन के दौरान शासकीय कार्यालय व उनके कार्य तो निर्बाध गति से चालू रहे है। फिर पीएम आवास योजना के प्रकरण स्वीकृति में कौनसी बाधा उतपन्न हुई है?

भूखण्ड भी आवंटित हो

थांदला नगरीय क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनेक ऐसे परिवार भी है, जिनके पास स्वयं के मकान तो दूर भूखण्ड भी नही होकर वे किराए के झोपड़ों में रहकर अपना जीवन यापन बमुश्किल कर रहे है। जबकि नगर में अनेक शासकीय आधिपत्य की भूमिया रिक्त पड़ी होकर उन पर योजनाबद्ध रूप से भूमाफिया कब्जा करते जा रहे है व कर चुके है ऐसी भूमियों को मुक्त करवाई जाकर आवासहीन परिवारों को पट्टा दिया जा सकता है। ये ही नही नगर में अनेक कालोनियां बनी है जिनमे शासन नियम अनुसार स्लम की भूमि को नाममात्र कीमत में गरीबो को आवंटित करने का प्रावधान है। परन्तु कालोनाइजरों द्वारा ऐसी स्लम कोटे की भूमि/प्लाट कमजोर वर्ग को आवंटित करने की बजाए बिक्री कर दी गई है। उन भूमियों को भी शासन को अधिग्रहित कर उन गरीबो को आवंटित करवाना चाहिए जिनके पास भूखण्ड नही है तभी पीएम आवास योजना का सही लाभ गरीबो को मिल सकेगा। अगर ऐसा होता है तो ÷हर गरीब का सपना, एक घर हो अपना÷ पूर्ण हो सकेगा।

नवागत थाना प्रभारी ने आते ही बाइक चोरों को पकड़ा

माही की गूंज, थांदला।

नगर में बीते कई माह से चोरों के हौसले बुलंद है, बदमाश दिनदहाड़े लूट, चोरी को अंजाम दे कर फरार हो जाते है। पिछले 2 माह में नगर के मंदिरों को भी चोरों ने निशाना बनाया, जिसका आज तक खुलासा नही हुआ। जिससे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान भी लगे। नवागत थाना प्रभारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के साथ बुधवार को पुलिस ने चोरो को पकड़ा। मामले में शकील मोहम्मद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि, मैं बाइक से आ रहा था कि नोगांवा नर्सरी के पास नगर के ही दो व्यक्ति चिरंजीत व दीपक पिता शांतिलाल राठौड़ ने रास्ता रोककर बाइक छीनकर मारपीट कर फरार हो गए। शकील मोहम्मद की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 444/2021 धारा 394 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर एसडीओपी मनोहर गवली के निर्देशन में टीम तैयार कर पुलिस की मुखबरी पर देवराज ढाबे से दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर उनके घर से 2 बाइक जप्त की गई।

जिला कलेक्टर ने रायपुरिया के विवादित मार्केट की चार दुकानों को किया निरस्त

दुकानदारों ने कहा हमारे पास पंचायत को किए भुगतान की रसीद, गलती की तो पंचायत जवाब दे

माही की गूंज, रायपुरिया।

ग्राम रायपुरिया में झाबुआ मार्ग पर बने मार्केट की लगातार शिकायत ओर जांच के बाद जिला कलेक्टर ने मार्केट की चार दुकानो को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। 15 जुलाई को कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत एवं ग्राम राजस्व अधिनियम 1993 की धारा 65 के तहत निहित ग्राम पंचायत ने नियमो को ताक में रखकर अवतरण की कार्रवाई की गई हैं। उक्त आदेश के अनुसार मार्केट की एक, दो, छः और नो की नीलामी प्रकिया निरस्त की गई है। आदेश के बाद ग्राम पंचायत सचिव का कहना है कि, कलेक्टर महोदय के आदेश का पालन करवाया जाएगा और निरस्त की गई दुकानदारों को नोटिस दिए जाएंगे। वही दुकानदारो का कहना है कि, हमने ग्राम पंचायत से विधिवत दुकानें ली है ओर हमारे पास भुगतान की रसीदे भी है, यदि कोई गलती हुई है तो उसका जवाब ग्राम पंचायत देगी।

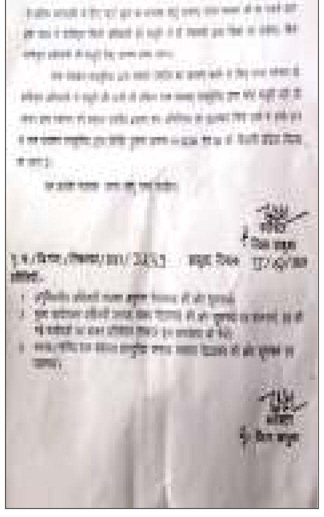

किसी भी योजना का लाभ देने से लेकर आईडी जोड़ने तक के ग्रामीणों से पैसे वसूलता है रोजगार सहायक

शिकायत करने पर भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष को दी धमकी, अधिकारीयों के कानों पर जु तक नही रेंग रही

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायकों का दबदबा और अधिकारियों से कमीशन की बंदरबाट इस कदर हावी है कि, उनकी किसी भी शिकायत का प्रभाव अधिकारीयो को नही पड़ता उल्टा रोजगार सहायक शिकायतकर्ताओं सहित सत्तापक्षीय नेताओ ओर संगठन के पदाधिकारियों तक को घमकाने से नही चूकते है। विकास खण्ड की ग्राम पंचायत सामली के रोजगार सहायक कैलाश सिंगाड को हटाने के लिए पंचायत के ग्रामीण लामबंद हुए और शिकायत अनुविभागीय अधिकारी, जनपद सीईओ को की गई, लेकिन कोई प्रभाव नही पड़ा। जिसके बाद मामला कलेक्टर तक पहुंचा जहां से जांच का आश्वासन देकर मामला वहीं पेटलावद के अधिकारियों के पास जांच के लिए भेज दिया, जिनके कानो तक पहले भी जुं नही रेंगी थी।

ग्रामीणों ने पंचायत के रोजगार सहायक पर आरोप लगाते हुए बताया कि, कैलाश सिंगाड आए दिन ग्रामीणों से भ्रष्टाचार और अभ्रद व्यवहार कर रहा है एंव इसकी दादागिरी चरम सीमा पर आ गई है एवं दादागिरी से आम जनता को डरा रहा है, वहीं ग्रामीणो से बिना लेनदेन से कोई कार्य नहीं करता है। ग्राम में किसी की मृत्यु हो जाने पर संबल योजानान्तर्गत दो लाख रूपए शासन से पात्र होने पर दिया जाता है, उसमें भी रोजगार सहायक द्वारा किसी से पचास हजार तो किसी से चालीस हजार रूपए की मांग की जाती है और अगर हितग्राही द्वारा राशि नहीं दी जाती तो उसको योजना का लाभ नहीं दिलावाया जाता है। जो हितग्राही राशि देने से मना करता है उसे डराया धमकाया जाता है कि, तेरा दुसरा कोई काम नही करूंगा। सामली में किसी की आईडी में नाम जोडना या हटवाना है तो रोजगार सहायक द्वारा प्रत्येक नाम के 150 से 200 रूपए की मांग की जाती है और पचास चक्कर लगाने के बाद भी रोजगार सहायक ग्रामीणों का कार्य समय पर नही करता और पैसो के लिए परेशान करता है।

भारतीय जनता पार्टी, रायपुरिया

रायपुरिया मंडल के उपाध्यक्ष गलिया डोडियार द्वारा कलेक्टर को की गई शिकायत की प्रति।

रोजगार गारंटी के काम हो रहे जेसीबी से, फर्जी हाजरी भरकर अंगूठा लगाने वाली मशीन से खुद निकलता है राशि

ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर जो आरोप लगाए है वो जांच का विषय है। ग्राम पंचायत सामली में रोजगार गारंटी के कार्यों में जेसीबी से हमेशा निमार्ण कार्य करवाया जाता है उसमें सहायक सचिव अपने परिवार या रिशतेदारो और अपने करीबियों के नाम से फर्जी मस्टर निकालकर हाजरी भर लेता है और राशि आधार कार्ड के जरिए रोजगार सहायक निकाल लेता है। सिंगाड फलिए में बनाई गई सुदुर सडक के संबंध में ग्रामीण मनु सिंगाड ने जानना चाहा कि, सड़क अधुरी पड़ी है आप इसे बनवा दो आने-जाने में परेशानी होती है। तो रोजगार सहायक पुरे परिवार को लेकर रात में मनु सिंगाड के घर मारने के लिए आ गया, चिलाने पर फलिया में रहने वाले और लोग भी आए तो रोजगार सहायक परिवार सहित अंधेरे में मौका देख भाग गया। मामले की शिकायत पुलिस में भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई वहां भी नही हुई।

ग्राम पंचायत सामली में सिंगाड फलिया से फलिया स्कुल तक सुदुर सड़क का निमार्ण कार्य किया जा रहा है जो करीब दिसम्बर 2020 से चल रहा है, लेकिन आज तक मजदुरी केवल कागज चल रही है और जेसीबी से पुरा रोड बनावा दिया फिर भी वह सड़क अधुरी पड़ा है। रोड का कार्य रोजगार सहायक की मनमर्जी से चल रहा है जब पैसे निकालना होते फर्जी मस्टर भर कर निकाल लेता है, ग्रामीणो द्वारा रोड के अधुरे निमार्ण की बात की जाती है तो लोगो से विवाद व झगडा किया जाता है। वर्तमान तक उक्त रोड फर्जी हाजरी पर चल रहा है जबकि मौके पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।

5 से 10 हजार, दो योजना में नाम जुड़वाओ बाकी कमीशन निर्माण कार्य मे

सामली के रोजगार सहायक ने सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए अपना खुद का सिस्टम बना रखा है। ग्रामीणों द्वारा शासन की किसी भी योजना का लाभ लेने की कोशिश की जाती है तो रोजगार सहायक द्वारा पहले पाच हजार की मांग की जाती है। जो व्यक्ति 5 हजार रूपए देता है उसका काम हो जाता है और योजना का लाभ मिलने पर पशु शेड, कपिलधारा जैसी योजनाओं की राशि के भुगतान के दौरान अलग से राशि वसुली जाती है, अगर रिश्वत पही दो तो रोजगार सहायक भुगतान रूकवा कर परेशान करता है। प्रधानमंत्री आवास के प्रति हितग्राहियो से प्रति किश्त पर दस-दस हजार रूपए लेता है और हितग्राहियों को राशि नहीं देता और गाली-गलौच करता है। उक्त रोजगार सहायक के कारण ग्राम पंचायत में नए पुराने आवास अब तक अधुरे पडे है। आवास हितग्राही अमरसिह पिता सावरणिया भुरिया निवासी ग्राम सामली के साथ भी क़िस्त का भुगतान करने का कहने पर रोजगार सहायक मारपीट कर चुका है।

भाई को दे रखी उचित मूल्य की दुकान, नही मिलता राशन

सामली में रोजगार सहायक ने अपने भाई को शासकीय उचित मुल्य की दुकान दिलवा रखी है उसमें भी जनता को समय पर गेहुँ, चावल, शक्कर, करोसीन नही दिया जाता है और उचित मुल्य दुकान में भी भारी भष्ट्राचार किया जाता है। गेहुँ, बाजारा आदी बाजार में बेचा जाता है और अनाज लेने वालो को डरा-धमकाकर भाग दिया जाता है। ग्राम पचायत सामली में सहायक द्वारा जो भी निमार्ण कार्य किया जाता है, उसमें भी भाई-भतिजावाद चलाकर अपने रिश्तेदारों से ही काम करवाया जाता है और दुसरे लोगों को भगाया जाता है।

मण्डल उपाध्यक्ष को दी जान से मारने की धमकी

ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत की जानकारी रोजगार सहायक को लगी तो, अपने तीन-चार साथियों के साथ शराब के नशे में रायपुरिया मण्डल के उपाध्यक्ष गलिया डोडियार की दुकान पर पहुँचकर उसे भी जान से मारने तक की धमकी दे डाली। विकास खण्ड में भ्रष्ट सीईओ के राज में रोजगार सहायक और सचिव इतने आश्वासत है कि, प्रशासनिक रूप से इन पर कोई कार्रवाई नही होगी, जिसके चलते लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं अपनी सरकार की साख बचाने के लिए भ्रष्टाचारियो पर कार्रवाई के लिए ग्रामीणों के साथ खड़े होने वाले जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी को धमकी देने वालो पर भी कोई कार्रवाई नही होती है, जिससे बड़े नेताओं की मंशा पर सवाल खड़ा होता है। मण्डल के उपाध्यक्ष ने स्वयं के लेटर पेड़ पर कलेक्टर को लिखित में रोजगार सहायक को हटाने और इसके कार्यकाल में हुए गबन की जांच की मांग की है, लेकिन 25 दिन का समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई कलेक्टर कार्यालय की और से देखने को नही मिली।

पुलिस रही नाकाम मुख्यमंत्री का पुतला दहन

माही की गूंज, खवासा

लात मार-मारकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन।

संविधान निर्माताओं ने स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए शसक्त विपक्ष को बहुत जरूरी बतलाया था और विपक्ष की यह जिम्मेदारी थी कि, वे जनहित में सरकार के कार्यो का संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन करे और जनहीत के मुद्दे पर सरकार को अपने लिए गए फैसले पर पूर्वविचार के लिए मजबूर करें। लेकिन विपक्ष से भी यह उम्मीद रखी है कि, वे विरोध तो करे लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर जिसमें धरना, रैली और हड़ताल शामिल है। संवैधानिक पदो पर बैठे व्यक्तियों का पूतला दहन आमतौर पर नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन की यह जिम्मेदारी होती है कि, ऐसा करने वालों को रोके। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर पुतला दहन न हो इसके लिए पुलिस मुस्तैद रहती है और पुलिस किसी भी किमत पर पुतला दहन नहीं हो इसके लिए वो कोई कसर पहीं छोड़ती है। लेकिन इस मामले में खवासा पुलिस का रवैया सुस्त ही रहा है। गत रविवार को कांग्रेस के नेतृत्व में बढ़ती पेट्रोल-डीजल व महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि, महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कोरोना में लॉकडाउन के चलते यहां व्यापार धंधे व नौकरी पेशा सहित आम लोगों को जीवन यापन करना कठिन साबित हुआ है, ऊपर से रसोई गैस सहित पेट्रोल-डीजल, खाद्य तेल, दाल आदि में तूफानी तेजी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और इसके विरोध स्वरूप उन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला दहन बीच चौराहे पर कर दिया और पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी। पुतला दहन से कांग्रेस ने जहां अपने विपक्षी होने का एहसास करवा कर सरकार की नीतियों की आलोचना की है वहीं पुलिस द्वारा पुतला दहन न रोका जाना पुलिस की कमजोर कार्यप्रणाली को दर्शाता है और इसकी चर्चा पूरे गांव में होती रही है।

पटवारी संघ ने नारेबाज़ी कर सौंपा ज्ञापन

जोबट पटवारी निलंबन पर संघ ने साधी चुप्पी

माही की गूंज, पेटलावद।

म.प्र. पटवारी संघ की पेटलावद तहसील इकाई के पटवारियों ने मंगलवार को लंबित विभिन्न मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि, शासन द्वारा विगत कई वर्षों से केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है, पर मांग पूर्ण नहीं की गई, जिससे प्रदेश के पटवारियों में निराशा का भाव होकर मनोबल प्रभावित हो रहा है। आए दिन पटवारियों की मौत हो रही है। उन्होंने बताया कि, विगत 22 वर्षो से पटवारी के वेतनमान का उन्नयन नहीं किया गया है, जबकि इसी अवधि में कई अन्य विभागों के कई समकक्ष कर्मचारी कैडरों जिनका वेतन तत्समय पटवारी से कम था के वेतनमान का उन्नयन किया जा चुका है, जबकि उपरोक्त समयावधि में पटवारी के कर्तव्यों तथा योग्यता में काफी बढ़ोतरी की गई है।

2007 में मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री द्वारा भी पटवारियों के वेतन उन्नयन की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व मंत्री द्वारा भी पटवारियों का वेतनमान 5200-20200, 2800 ग्रेड पे किए जाने हेतु वर्ष 2019 में लिखित आश्वासन पत्र दिया गया है, किंतु अभी तक 5200-20200, 2800 ग्रेड पे वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ है। शासन नियमानुसार पदोन्नाति के सापेक्ष में पटवारी संवर्ग को प्रथम समयमान में राजस्व निरीक्षक एवं द्वितीय में नायब तहसीलदार, सहायक अधिक्षक भू-अभिलेख एवं तृतीय में तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख का वेतनमान प्राप्त होना चाहिए जो कि वर्तमान में पटवारी संवर्ग को प्राप्त नहीं हो रहा है। वर्तमान में पटवारियों की नवीन भर्ती प्रदेश स्तर पर की गई है जबकि पटवारी का पद जिला स्तरीय है तथा कई जिलों के विखंडन किए जाने के फलस्वरूप वर्तमान में नवनियुक्त कई पटवारी अपने गृह जिले से लगभग 800 किलोमीटर दूर तक पदस्थ होकर कार्यरत हैं। स्थिति यहां तक है की दूरी अधिक होने से लगभग 15 पटवारियों की मौत हो चुकी हैं। अतः ऑनलाइन प्रक्रिया संपादन कर पति-पत्नी को शासन की मूलभावना निर्देशानुसार एक जगह पदस्थ करने व प्रदेश भर में बाहर पदस्थ नवनियुक्त पटवारियों को उनके गृह जिलों में पदस्थ किया जाए, ताकि वे अपने पारिवारिक दायित्वों का पालन कर सकें और चिंता मुक्त होने से उनकी कार्यक्षमता व कार्यकुशलता में और अधिक वृद्धि हो। नवीन पटवारियों की सीपीसीटी की अनिवार्यता संबंधी नियम समाप्त किया जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि, वर्तमान में नवनियुक्त पटवारियों में से लगभग 75 फीसद पटवारियों द्वारा सीपीसीटी उत्तीर्ण की जा चुकी है। कोरोना संकंट होने के कारण प्रदेश स्तर पर विगत दो वर्षों से उपरोक्त परीक्षा शासन स्तर से न होने से लगभग 25 प्रतिशत पटवारियों को परिक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि समस्त नव नियुक्त पटवारियों द्वारा सभी विभागीय कार्य ऑनलाइन पूरी कुशलता से किए जा रहे हैं। मांग की गई है कि, पटवारियों को सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के अंदर सभी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो म.प्र. पटवारी संघ प्रदेश व्यापी आंदोलन करने को बाध्य होगा।

जोबट मामले में साधी चुप्पी

जैसे ही पटवारी संघ ने ज्ञापन देने की बात कही प्रशासन हरकत में आ गया। नेमावर मामले सहित अन्य मामलो में मंच साझा करने और भड़काऊ भाषण देने पर जोबट पटवारी अलावा के निलंबन के बाद राजनीति गर्मा गई। ऐसे में पटवारी संघ के ज्ञापन पर कयास लगाए जा रहे थे कि, संघ की और से पटवारी के निलंबन का विरोध दर्ज करवाया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ देखने को नही मिला। पेटलावद पटवारी संघ अध्यक्ष ने साफकहा कि, ज्ञापन केवल हमारी मांगो को लेकर है, पटवारी के निलंबन मामले में हमारा कोई विषय नही है।

क्या सन्नी की मौत नही थी दुर्घटना?

परिवार की मांग के बाद जांच में लिया मामला, पुलिस ने बिना जांच पड़ताल ही मान लिया दुर्घटना

माही की गूंज, पेटलावद।

22 जून रात्रि को रायपुरिया के युवक उपेन्द्र उर्फ सन्नी सिसोदिया के मौत के मामले में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। परिवार द्वारा लगाए गए आरोप और गूंज को अब तक मिली जानकारी के बाद मामले में एक बात तो साफहै कि, 22 जून की रात्रि जो कुछ भी घटा उसे सीधा-सीधा दुर्घटना कहीं से कहीं तक नही कहा जा सकता है। परिवार के जवान बेटे को खोने वाले सन्नी के पिता धर्मेंद्र सिसौदिया और उसकी बहन आज भी सन्नी की मौत के पीछे के असली कारण जानने में लगे हुए है और हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे कोई न कोई सुराग मिल जाए जिससे मौत की असली वजहों तक पहुँचा जा सके।

रायपुरिया पुलिस की लापरवाही हुई उजागर, शंका जाहिर करने के बाद भी नही की गई जांच

अब तक देखा जाए तो पुलिस की प्राथमिक जांच पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सन्नी की मौत अगले ही दिन अंतिम संस्कार के बाद परिवार ने रायपुरिया पुलिस के सामने मौत के पीछे दुर्घटना नही होने की शंका जाहिर की थी, लेकिन पुलिस जो कि घटना को दुर्घटना मान चुकी थी, मौके से कोई जरूरी शाक्ष नही जुटाए, जिससे मामले की जांच में पारदर्शिता आ सके। मुख्य रूप से फोरेंसिक टीम और डॉग स्कवाड को मौके पर नही लाया गया न ही मौके से पुलिस ने कोई सामान जप्त किया। पुलिस ने ये तक जानने की कोशिश नही की कि, वाहन में बैठा एक अकेला ड्राइवर वाहन के दूसरे हिस्से में कैसे दब गया।

परिवार की मांग के बाद रायपुरिया पुलिस जांच की बात करती रही लेकिन कोई खास सक्रियता नही दिखी। जिसके बाद परिवार ने सन्नी की मौत के चौथे दिन 26 जून को थाना रायपुरिया में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर जांच की मांग करी, लेकिन पुलिस ने परिवार के आवेदन के बाद युवक का साथी जो कि, उस दिन उसके साथ था उसको बुलाकर उसके बयान दर्ज कर इतिश्री कर दी। न बारीकी से जांच हुई न सख्ती से पूछताछ, जो कुछ मृतक के साथी ने बताया उससे मानकर पुलिस ने मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। थाने की जांच से असंतुष्ट परिवार ने करणी सेना के माध्यम से एसडीओपी पेटलावद को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मृतक के साथी पर नामजद हत्या करने या शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए। परिवार द्वारा एसडीओपी सौनु डावर से मुलाकात कर दुर्घटना को हत्या होने तक के प्रयाप्त तथ्य दिए, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

दुर्घटना स्थल से मिला सन्नी के साथी का जूता।

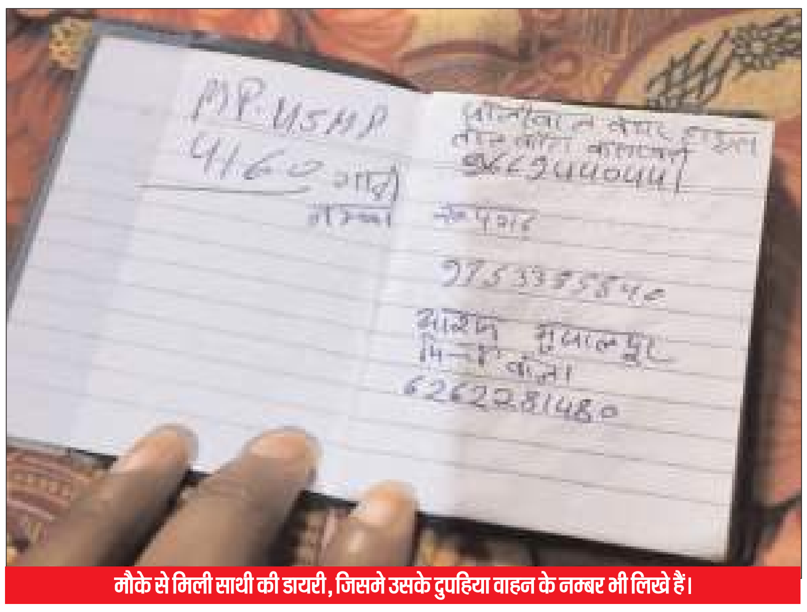

मौके से मिली साथी की डायरी, जिसमे उसके दुपहिया वाहन के नम्बर भी लिखे हैं।

पुलिस ने कहा सन्नी ने पी रखी थी शराब, पीएम रिपोर्ट में नही है उल्लेख

मामले में थाना प्रभारी पंवार से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि, मामले की जांच बारीकी से की जा रही है और सारे तथ्यो को जोड़ा जा रहा है। सन्नी और उसके साथी की कॉल डिटेल के साथ-साथ व्हाट्सएप स्टेटस की स्थिति, मोबाइल लोकेशन और मामले से जुड़े पक्षो के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी का कहना है कि, अभी तक जांच में पता चला है कि, सन्नी ने माँगरोद के एक ढाबे पर शराब पी, उसके बाद झकनावद फंटे पर शराब पी और उसके साथी रमेश भूरिया को उमरकोट उतार दिया और रास्ते मे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रोड एक्सीडेंट होना बताया गया है। लेकिन पुलिस द्वारा जो बताया जा रहा हैं कि, इस संबंध में माँगरोद ढाबे से भी बयान दर्ज किए जाएंगे। पुलिस का कहना है, शराब पीने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नही करती, क्योकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक सन्नी के नशे में होने की कोई पुष्टि नही की है। वही सन्नी के पिता का कहना है कि, सन्नी शराब पीता हैं ये सत्य है लेकिन मौत के दिन न तो सन्नी ने व न ही साथी रमेश भूरिया ने माँगरोद ढाबे पर शराब पी, जिसकी जानकारी हमने ढाबा संचालक से भी ली है।

मृतक उपेंद्र उर्फसन्नी सिसोदिया।

जूता और डायरी अहम सुबूत हो सकते थे

पुलिस की कहानी और मृतक के साथी रमेश भूरिया के बयान के हिसाब से रमेश भूरिया लौटते समय उमरकोट अपने रिश्तेदार के यहां चला गया था। रमेश ने पुलिस को बताया कि, सन्नी से उसकी गाड़ी चलाने को लेकर बहस हो गई थी जिसके बाद उसे सन्नी ने उमरकोट में उतार दिया था और वो वहां से अपने रिश्तेदार के यहां चला गया था। लेकिन रमेश की इस कहानी पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि रमेश न केवल सन्नी का दोस्त था बल्कि परिवार के सदस्य जैसा था और परिवार के साथ आया-जाया करता था। रमेश के सन्नी के साथ होने तक कि जानकारी परिवार को नही थी, सन्नी के मामा द्वारा दुर्घटना में रमेश को कितनी चोट लगी और उसकी क्या हालत है ये पूछने पर पता चला कि, सन्नी के साथ रमेश भी था क्योंकि लौटते समय दोनों अमझेरा में मामा के यहाँ रुके थे। दुर्घनाग्रस्त वाहन टवेरा के पास केवल मृतक सन्नी मिला, जबकि साथी रमेश की डायरी और एक जूता भी वाहन में ही मिला। जिससे ये कह पाना मुश्किल है कि, दुर्घटना या किसी वारदात के समय रमेश वाहन में नही था। परिवार द्वारा जुते ओर डायरी पर सवाल खड़े करने पर भी पुलिस ने मौके पर जप्त नही किए और मौके पर छोड़ दिए। जिसे बाद परिवार ने ही इन सबूतों को अपने पास रखा।

दुर्घटनाग्रस्त वाहन।

परिवार का सदस्य होने के बाद भी अंतिम संस्कार में नही पहुँचा दोस्त

सन्नी के परिवार का बेहत ही करीबी रमेश भूरिया जिस पर परिवार ने सीधा शक जताया है उसके पीछे बड़ा कारण उभर कर आया है वो ये कि, सन्नी की मौत के बाद रमेश अपने दोस्त सन्नी के अंतिम संस्कार तक मे नही पहुँचा।

सन्नी के पिता ने बताया कि, रमेश परिवार के अहम सदस्य की तरह होने के बाद भी सन्नी की मौत के सात दिन बाद बैठने के लिए घर आया और बेहत ही घबराया हुआ था, जब उससे इतने दिन तक नही आने का कारण पूछा तो उसने यही बताया कि, उसे सन्नी की मौत की जानकारी नही थी। सन्नी के पिता ने कहा कि, रमेश के चहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी और सवाल करने पर खुद के उमरकोट उतरने का बोल कर चला गया।

मामले में जांच में जुटी एसडीओपी सौनु डावर ने बताया कि, मामले की जांच बारीकी से की जा रही है, मोबाइल डिटेल के साथ एक्सपर्ट का व्यु भी लिया जाएगा, जिसके बाद ही आगे की जांच की जाएगी, पुलिस मामले को फिलहाल दुर्घटना ही मान रही है लेकिन किसी वारदात या घटना होने से भी इंकार भी नही कर रही हैं।

सन्नी की मौत के पीछे क्या छुपा है कोई बड़ा जुर्म, क्या लूट का शिकार हुआ सन्नी या फिर दुर्घटना के बाद मदद मांगना पड़ा भारी, साथ ही उन सवालों को फेहरिस्त जो सन्नी अपनी मौत के बाद छोड़ गया, साथी रमेश छुपा रहा है कोई बड़ी घटना, क्या पुलिस के हाथ लगे हैं अहम सबूत।

करेगे अगले अंक में बड़ा खुलासा...

संपादकीय

गुल खिला सकती है कैप्टन की गुगली

पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व युद्ध के निष्कर्ष में भले ही कहा जा रहा हो कि, कैप्टन अमरिंदर से लड़ाई में नवजोत सिंह सिद्धू असरदार साबित हुए और बाजी मार ली, लेकिन यह निष्कर्ष इस टकराव की सरल व्याख्या होगी। अब चाहे टकराव को टालने के लिए सिद्धू की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी कर दी गई हो, लेकिन वे इस पिच पर आसानी से चौके-छक्के लगा पाएंगे, कहना कठिन है। हालांकि, जातिगत, क्षेत्रगत व अन्य समीकरणों को साधने के लिए चार कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं, लेकिन दशकों से पंजाब की राजनीति की नब्ज पर हाथ रखने वाले राजनीति के पुराने खिलाड़ी कैप्टन को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिद्धू ने भले ही लंबे अरसे क्रिकेट खेला है, लेकिन कैप्टन ने लंबी पारी राजनीति में खेली है। कहा जा रहा है कि, इस प्रकरण में कांग्रेस आलाकमान ने परिपक्व रणनीति नहीं दिखाई। वह भी ऐसे वक्त में जब पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही माह बाकी हैं। दोनों दिग्गजों में वार-तकरार का कोई अच्छा संदेश कम से कम जनता में तो नहीं ही गया है। वह तो कांग्रेस की किस्मत अच्छी है कि, तीन कृषि सुधार कानूनों के चलते भाजपा पंजाब में हाशिए पर है और अकाली दल पूरी तरह चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पंजाब में वह जमीन तैयार नहीं कर पाई है जो कांग्रेस के मुकाबले के लिए सामने खड़ी हो सके। बहरहाल, यह कहना जल्दबाजी होगी कि, कांग्रेस आलाकमान के मौजूदा फार्मूले से पार्टी में पैदा वर्चस्व का संकट खत्म हो जाएगा। पंजाब की राजनीति के पुराने अनुभवी खिलाड़ी कैप्टन अमरिंदर इस बदलाव को सहजता से स्वीकार कर लेंगे, यह समस्या के समाधान की सतही व्याख्या होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि, कैप्टन की तरफ से कोई चौंकाने वाली पहल हो सकती है। पंजाब के सांसदों की पिछले दिनों जारी सक्रियता भी कोई गुल खिला सकती है। अब चाहे लच्छेदार भाषा बोलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने फिलहाल पंजाब की राजनीति में बढ़त ले ली हो, लेकिन हकीकत यह है कि, क्रिकेट से राजनेता बने सिद्धू राजनीति की चौसर पर कैप्टन अमरिंदर के मुकाबले उन्नीस ही साबित होंगे। इसमें दो राय नहीं कि, कैप्टन भले ही कांग्रेस आलाकमान के फैसले से सतही तौर पर सहमति जता रहे हों, लेकिन उनकी अनदेखी करते हुए जो कुछ हुआ जाहिर तौर पर उन्हें नागवार गुजरा होगा। पहले भी कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का अध्यक्ष बनाने पर सहमति तो जताई थी लेकिन शर्त रखी थी कि, पिछले कुछ समय में सिद्धू द्वारा उनके खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों पर वे सार्वजनिक माफी मांगें। लेकिन वास्तव में उनकी शर्त पर पार्टी आलाकमान ने कान नहीं धरा। कांग्रेस पार्टी को नहीं भूलना चाहिए कि, देश में जब-जब कांग्रेस विरोधी लहर रही, तब-तब कैप्टन पार्टी को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। यहां तक की देशव्यापी मोदी लहर में भी वे पार्टी की नैया पार लगाने में कामयाब रहे हैं। वर्ष 2017 में भी अपने बूते उन्होंने पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि, हालिया घटनाक्रम से वे आहत हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि, वे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। दरअसल पंजाब की राजनीति के हिसाब से यह बेहद संवेदनशील समय है और कैप्टन सरकार का कार्यकाल करीब छह माह ही रह गया है। जाहिर तौर पर हालिया बदलाव से कैप्टन ने खुद को आहत महसूस किया होगा। ऐसे में अकसर विवादों में रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष के रूप में निष्कंटक पारी खेल पाएंगे, कहना मुश्किल है। उन्हें सत्ता की पिच पर कैप्टन की नित नई गुगली के लिए तैयार रहना होगा। वैसे भी राजनीति में कहने-सुनने और करने की हकीकत में कब साम्य नजर आया है। यह हर बार संभव नहीं कि, युवा विकल्प अनुभवी विकल्प का पर्याय बन सके। कैप्टन ने पंजाब की राजनीति को गहरे तक जीया है। अनुभव के दांव का कोई विकल्प न जीवन में है और न ही राजनीति में।

नई तकनीकों के सृजन में देश का भविष्य

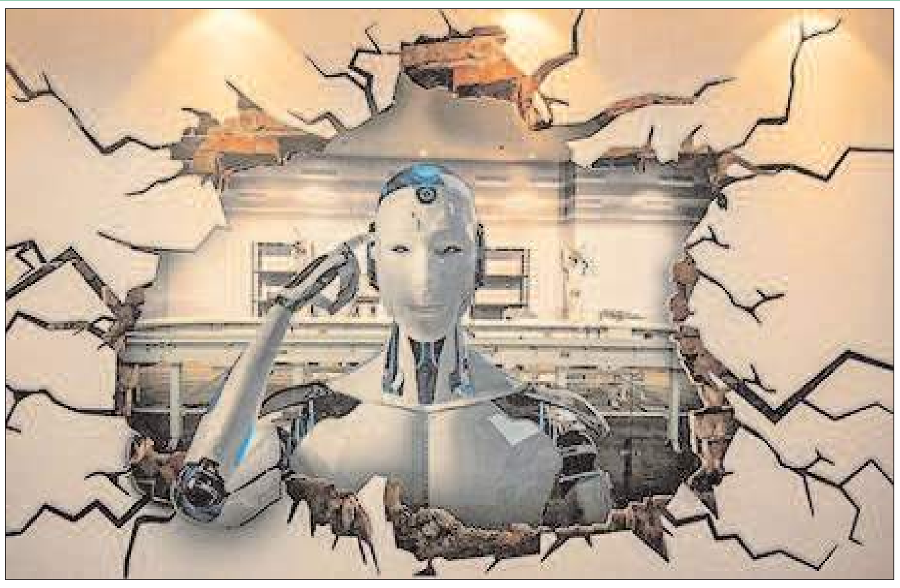

भरत झुनझुनवाला

तकनीकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम पिछड़ते जा रहे हैं। चीन ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर अपना यान उतारा है, सूर्य के ताप के बराबर का ताप अपनी प्रयोगशाला में बना लिया है और लड़ाकू विमानों को राफेल या दूसरी कंपनियों से खरीदने के स्थान पर स्वयं बनाने में सफलता हासिल की है। यदि हमें तकनीकों के क्षेत्र में अपनी पैठ बनानी है तो नई तकनीकों के सृजन में भारी निवेश करना जरूरी होगा। लेकिन कोविड के इस काल में वर्तमान चालू खर्चों को सरकार पोषित नहीं कर पा रही है। यद्यपि वर्तमान वर्ष 2021-2022 के बजट में केंद्र सरकार ने पूंजी खर्चों में लगभग 35 फीसदी की वृद्धि की है और वर्तमान वर्ष में 5.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी खर्च करने का प्रस्ताव है परंतु यह फलीभूत होगा कि नहीं, यह निश्चित नहीं है। इस निवेश में नई तकनीकों का क्या हिस्सा है, यह भी स्पष्ट नहीं है। सच यह है कि, आने वाले समय में तकनीकों का ही बोलबाला होगा। जिस देश के पास आधुनिकतम तकनीकें होंगी वही विजयी होगा। हम देख चुके हैं कि, किस प्रकार अमेरिका की आधुनिक पैट्रियट मिसाइलों ने सद्दाम हुसैन के इराक की सेना को चंद दिनों में ही ध्वस्त कर दिया था। इसलिए हमें तकनीकों में भारी निवेश करना होगा। प्रश्न है कि, इसके लिए रकम कहां से आए?

सरकारी इकाइयां तीन प्रकार की हैं। पहली इकाइयां सार्वजनिक सुविधाओं को प्रदान करने वाली हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफइंडिया हर जिले में क्लीयरिंग हाउस चलाता है अथवा जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफसेकेंडरी एजुकेशन द्वारा पूरे देश के विद्यालयों को नियमित किया जाता है। इस प्रकार की सार्वजनिक इकाइयों को बनाए रखना जरूरी है। इन कार्यों को निजी हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी इकाइयां वे हैं, जिनके समकक्ष निजी इकाइयां वर्तमान में सफल हैं। जैसे स्टेट बैंक को छोड़कर अन्य बैंकों के सामने कोटक महिंद्रा आदि प्राइवेट बैंक सफल हैं; अथवा जैसे एयर इंडिया के सामने इंडिगो एवं स्पाइस जेट एयरलाइन सफल है; अथवा जैसे तेल कंपनियों में इंडियन ऑयल के सामने रिलायंस सफल है। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक इकाइयों को बनाए रखने का औचित्य नहीं है क्योंकि इन सेवाओं को निजी उद्यमी उपलब्ध करा सकते हैं। यह सही है कि, निजी उद्यमियों द्वारा जनता से अधिक रकम वसूल कर मुनाफाखोरी की जा सकती है लेकिन इस समस्या को नियंत्रण व्यवस्था सुदृढ़ करके संभाला जा सकता है। जैसे ट्राई ने मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली निजी कंपनियों पर नियंत्रण कर देश में सस्ती मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इसी प्रकार रिज़र्व बैंक द्वारा निजी बैंकों के नियंत्रण से सस्ती बैंकिंग सेवाएं प्रदान कराई जा सकती हैं। इस प्रकार की तमाम इकाइयों का निजीकरण किया जा सकता है, जिनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जा सकी हैं। वर्तमान में सार्वजनिक इकाइयों का ÷मार्केट कैपिटलाइजेशन÷ यानी उनके शेयरों की बाजार में कीमत लगभग 20 लाख करोड़ है। इसके सामने वर्तमान वर्ष 2021-2022 में सरकार द्वारा कुल पूंजी खर्च केवल 5.5 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। अतः यदि वर्तमान सार्वजनिक इकाइयों का निजीकरण कर दिया जाए तो हमें 20 लाख करोड़ की विशाल रकम मिल सकती है। इसमें यदि एक-चौथाई इकाइयां जैसे स्टेट बैंक को मान लें, जिनका निजीकरण नहीं करना चाहिए; तो हमें लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की विशाल रकम मिल सकती है।

इस विशाल रकम को हमें नई तकनीकों के सृजन में तत्काल निवेश करना चाहिए। जैसे एक इकाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा सकती है। वर्तमान में मेडिकल आदि क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से डॉक्टरों द्वारा पर्चे आसानी से लिखे जा रहे हैं और रोगियों को लाभ मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रोगी के तमाम टेस्ट का अध्ययन करके डॉक्टर को सुझाव दिया जाता है। इससे डॉक्टर के लिए तमाम टेस्ट रिपोर्ट को स्वयं देखना आवश्यक नहीं रह जाता है। दूसरे, छठी पीढ़ी के इंटरनेट के सृजन के लिए हमें निवेश करना चाहिए। तीसरे, इंटरनेट ऑफथिंग्स जैसे इंटरनेट के माध्यम से किसी दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था को संचालित करना, एयर कंडीशनिंग को नियंत्रित करना इत्यादि में निवेश करने में बहुत संभावनाएं हैं। चौथा, आने वाले समय में जेनेटिक जीन परिवर्तन से नई दवाएं इत्यादि बनाई जा रही हैं, जिस पर भी हमें निवेश करना चाहिए। जैसे आलू की प्रजाति में सुधार करके उसके माध्यम से विटामिन परोसा जा सकता है। पांचवां आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी जैसी वैकल्पिक दवाओं के विस्तार के लिए हमें इकाई बनानी चाहिए जो कि, इन उपचार व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार करें और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इन पर शोध करें इत्यादि। छठा, अमेरिका की वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने अंतरिक्ष में वाणिज्य यान भेजने का ऐलान किया है, इसी प्रकार भारत सरकार भी एक इकाई बना सकती है। वर्तमान में इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन द्वारा दूसरे देशों की सेटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया जा रहा है, यही कार्य एक अलग इकाई द्वारा किया जा सकता है। चीन ने मंगल ग्रह पर अपना यान उतारा है। भारत भी वाणिज्यिक स्तर पर अंतरिक्ष एवं दूसरे ग्रहों में यान भेज सकता है। इन तमाम तकनीकी संभावनाओं को फलीभूत करने के लिए जरूरी है कि, देश वर्तमान की तुलना में नई तकनीकों के सृजन में 10 गुना निवेश बढ़ाए। सरकार के वर्तमान बजट के अंतर्गत यह संभव नहीं है। इसलिए सरकार को कठोर कदम उठाते हुए स्टेट बैंक को छोड़ कर अन्य सरकारी बैंकों, एयर इंडिया, तेल कंपनियों आदि का निजीकरण कर देना चाहिए और मिली हुई रकम को नई तकनीकों के आविष्कार में निवेश करना चाहिए।

इस सुझाव के विपरीत कहा जा सकता है कि, जो सार्वजनिक इकाई के समीप हैं, उनके हितों को संरक्षित करने के लिए इनका निजीकरण नहीं होना चाहिए। पर यह तर्क नहीं ठहरता क्योंकि इकाई का निजीकरण किया जा रहा है, कर्मचारियों को सेवानिवृत्त नहीं किया जा रहा है। जो भी उद्यमी इन इकाइयों को खरीदेगा, उसे भी कर्मचारी की जरूरत होती है। यदि कर्मचारी ईमानदारी से काम करेंगे तो उन्हें वह निकाले, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अतः इस समय सार्वजनिक इकाइयों के श्रमिकों के हित साधने के स्थान पर सरकार को देश का तकनीकी भविष्य साधना चाहिए और तमाम गैर आवश्यक सार्वजनिक इकाइयों का निजीकरण करके उस मिली रकम को नई तकनीकों के आविष्कार में लगाना चाहिए।

महंगाई की मार

सिद्धार्थ शंकर

महंगाई के मोर्चे पर जनता को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। हर दिन डीजल-पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं। शायद ही कोई वस्तु हो, जिसके मूल्य न बढ़ा हों। मगर सबसे अधिक बढ़ोतरी खाद्य तेलों और ईंधन में हुई है। यह तब है, जब कोरोना महामारी के कारण लोगों की कमाई कम हुई है और उन्होंने खर्च को लेकर अपने हाथ रोक रखे हैं, यानी मांग में उछाल नहीं आ रहा। फिर रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दरें सबसे निचले स्तर पर स्थिर कर दी हैं। महंगाई बढ़ने के दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। एक, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और दूसरा विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में लागत बढ़ना। डीजल-पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अनेक स्तरों पर पड़ता है, उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन लागत और ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है, जिससे स्वाभाविक ही उनकी कीमतें बढ़ती हैं। मगर ईंधन की कीमतों पर अंकुश लगाने की कोशिशें विफल ही साबित हुई हैं।

लोगों पर महंगाई की सबसे बड़ी मार दैनिक इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की वजह से पड़ रही है। सब्जी, दालें, दूध, अंडे, खाद्य तेल और अनाज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि इनके उत्पादन के मामले में कोई कमी नहीं देखी गई है। किसान परेशान हैं कि, उनकी फसलें बाजार तक नहीं पहुंच पा रहीं, इसके चलते बहुत सारे किसान अपनी कच्ची फसलें, जैसे टमाटर, सड़कों के किनारे फेंकने पर मजबूर हुए, इसी तरह दालों का उत्पादन बेहतर रहा। अंडा उत्पादक आंदोलन तक कर चुके हैं कि, उनकी आपूर्ति बेहतर की जाए फिर भी कीमतें काबू में नहीं आ पा रहीं, तो साफहै कि, यह समस्या चीजों के अभाव की वजह से पैदा नहीं हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर में उस तरह लॉकडाउन भी नहीं लगा, जैसे पहली लहर में लगा था, जिससे आपूर्ति शृंखला बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हो। फिर भी महंगाई बढ़ रही है, तो इसका प्रमुख कारण यही है कि, इसे रोकने के लिए जो व्यावहारिक कदम उठाए जाने चाहिए थे, वे नहीं उठाए गए हैं।

कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार और नौकरियां चली गई हैं, लाखों लोगों के वेतन कम हो गए हैं, बड़े पैमाने पर कल-कारखाने बंद हुए हैं, बहुत सारे लोग अपने गांव लौटने पर मजबूर हुए हैं। ऐसे में पहले ही उन्हें अपने बच्चों की फीस, दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिस पर महांगाई की मार ने उन्हें और बेहाल कर दिया है। जिन छोटे-मोटे, रेहड़ी-पटरी के कारोबार, मिस्त्रीगीरी और दिहाड़ी करने वालों ने जैसे-तैसे फिर से जिंदगी को पटरी पर लौटाने का साहस जुटाया है, उन्हें भी बेहतरी की कोई सूरत नजर नहीं आती उनके कारोबार में लागत बढ़ रही है, यातायात और दैनिक खर्च बढ़ गया है और बचत काफी घट गई है। सरकार अगर कम से कम खाने-पीने की चीजों की कीमतें काबू में रखने में कामयाब हो जाती, तो भी लोगों को इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। महंगाई के मोर्चे पर चुनौतियों को दूर करने के गंभीरता से प्रयास नहीं किए जाएंगे, तो आर्थिक मोर्चे पर बेहतरी के सपने भी शायद ही पूरे हों। इस वक्त महंगाई पर काबू पाना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। उस पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और प्राकृतिक गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब लगभग पूरे देश में पेट्रोल की कीमत सौ रुपए से ऊपर पहुंच गई है और डीजल भी उसी के नक्शे-कदम पर चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही रसोई गैस के सिलिंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी की गई थी, अभी प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी और पाइप के जरिए घरों में पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस यानी पीएनजी की दरों में भी इजाफा कर दिया गया है। स्वाभाविक ही, इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। कोरोना काल में बाजार, कारोबार, उद्योग-धंधे बंद होने की वजह से लाखों लोगों के रोजगार छिन चुके हैं, लाखों लोगों की वेतन वाली नौकरियां जा चुकी हैं, निजी संस्थानों में कर्मचरियों के वेतन में भारी कटौती की गई है, जो फेरी लगाने, मिस्त्रीगीरी, इधर से उधर सामान पहुंचाने वगैरह का काम किया करते थे, उनके धंधे में भारी गिरावट आई है। ऐसे में देश के हर वर्ग के सामने अपने दैनिक खर्च में संतुलन बिठाना मुश्किल हो रहा है। जिस पर पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस आदि की ऊपर चढ़ती कीमतें उनकी चुनौतियां और बढ़ा रही हैं।

पर्यावरण संकट

खेती से जुड़ी हर गतिविधि को भारत में उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा है। ऋतुओं के अनुसार खेती की वैज्ञानिक परंपरा भी है। अन्न से काबोर्हाइड्रेट, दालों से प्रोटीन, फल-सब्जियों से विटामिन सभी भारत की भोजन की थाली में मिलता है। और यह सब मेहनतकश किसानों द्वारा देश को उपलब्ध करवाया जाता है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी (यानी नौकरी) ऐसी कहावत देश में प्रचलित रही है। किसान खेती में नयी-नयी खोजें करते हुए उत्पादन बढ़ाता रहा है। किसान की हालत कैसी भी रही हो, खेती को आज भी एक पवित्र व्यवसाय माना जाता है। लेकिन, आजकल औद्योगिक कृषि के पैरोकार उसी जीवनदायिनी खाद्य एवं पौष्टिकतापूरक परंपरागत कृषि पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। बागपत से लेकर ग्रेटर नोएडा तक के कोई एक सौ साठ गांवों में हर साल सैकड़ों लोग कैंसर से मर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोगों को लीवर और आंत का कैंसर हुआ है। बाल गिरना, किडनी खराब होना, भूख कम लगना, जैसे रोग तो यहां हर घर में हैं। सरकार कुछ कर रही है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी कुछ नोटिस ले रहा है, लेकिन इलाके में खेतों में छिड़के जाने वाले जहर की बिक्री की मात्रा हर दिन बढ़ रही है। दुखद है कि अब नदियों के किनारे विष-मानव पनप रहे हैं, जो कथित विकास की कीमत चुकाते हुए असमय काल के गाल में समा रहे हैं। वैश्विक कॉरपोरेट बिल गेट्स परंपरागत कृषि को पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक बता रहे हैं। वे चाहते हैं कि कृषि के तौर-तरीकों में परिवर्तन किये जायें, ताकि पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। बिल गेट्स का सुझाव है कि ऐसे बीज, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, इस्तेमाल किये जाएं, जिससे छोटे किसान ज्यादा से ज्यादा उपज ले सकें और आमदनी बढ़ा सकें। वे ज्यादा उपज के लिए जीएम फसलों, राउंडअप सरीखे खतरनाक खरपतवार नाशक और कीटनाशकों की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। पर्यावरणीय संकट से पार पाने के लिए जो उनका सुझाव कि छोटे किसान परंपरागत खेती और पशुपालन त्याग कर उनके सुझाये गये उपायों, बीजों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों को अपनायें, यह किसी भी हालत में कल्याणकारी नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा कि दुनिया में पर्यावरण संकट अमीर मुल्कों द्वारा अत्यधिक ऊर्जा और वस्तुओं की खपत और उससे होनेवाले उत्सर्जन के कारण है। अंतरराष्ट्रीय बाजार गुणवत्ता, उपभोक्ता और प्रशोधन जैसे नारों पर खेती चाहता है, जबकि हमारी परंपरा धरती को माता और खेती की पूजा करने की रही है। हमारे पारंपरिक बीज, गोबर की खाद, नीम, गौमूत्र जैसे प्राकृतिक तत्त्वों के कीटनााशक शायद पहले से कम फसल दें, लेकिन यह तय है कि इनसे जहर नहीं उपजेगा। छोटे किसानों को दोषी मानकर गलत दिशा में कृषि को मोड़ना दुनिया के लिए भारी संकट का कारण बन सकता है।

लाइलाज महामारी बनेगा, प्रकृति का बिगड़ता मिजाज !

ऋतुपर्ण दवे

प्रकृति पर कब किसका जोर रहा है? न प्रकृति के बिगड़े मिजाज को कोई काबू कर सका और न ही फिलाहाल मनुष्य के वश में दिखता है। हां, इतना जरूर है कि, अपनी हरकतों से प्रकृति को हमारे द्वारा लगातार नाराज जरूर किया जा रहा है जिस पर प्रकृति का विरोध भी लगातार दिख रहा है। लेकिन बावजूद इसके हम हैं कि मानते नहीं। न पर्यावरण विरोधी गतिविधियों को कम करते हैं और न ही प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को ही रोक पाते हैं। प्रकति और मनुष्य के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जहां प्रकृति की नेमत में लगातार कमीं आ रही है वहीं लगता नहीं कि, उसका अभिशाप भी खूब रंग दिखा है? नतीजा सामने है, गर्मियों में बरसात, बरसात में गर्मी और ठण्ड में पसीने के अहसास के बावजूद हमारा नहीं चेतना एक बड़ी लापरवाही बल्कि आपदा को खुद न्यौता देने जैसा है, हो भी यही रहा है।

सच तो यह है कि, प्रकृति की अपनी प्राकृतिक वातानुकूलन प्रणाली है जो बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, नतीजन हालिया और बीते कुछ दशकों में मानसून का बिगड़ा मिजाज सामने है। जब जरूरत नहीं थी तब जून में झमाझम बारिश हुई। अब जरूरत के वक्त कई जगह सूखा तो कहीं बाढ़ के विकराल हालात बन चुके हैं। यानी प्रकृति का खुद का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार तापमान में वृद्धि के कारण विश्व स्तर पर पानी की कमीं और सूखे का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। ये दोनों ही मानवता को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार से मुंह बाएं खड़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि, 1998 से 2017 के बीच बिगड़ैल मानसून से 124 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हो चुका है और करीब डेढ़ अरब लोग भी प्रभावित हुए हैं। एक अन्य ताजे भारतीय शोध से भी पता चलता है कि, हिमालय और काकोरम में ग्लोबल वार्मिंग का असर साफदिखने लगा है। ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ और रोजगार दोनों पर ही खतरा सामने है। पहले जून में पिघलने वाले ग्लेशियर अब अप्रेल में ही पिघलने लगे हैं। गर्मी से टूट रहे ग्लेशियरों से लगभग 100 करोड़ लोगों के सामने खतरे जैसे हालात दिखने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ही पूर्वानुमान है कि, ज्यादातर अफ्रीका फिर मध्य और दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप, मेक्सिको और शेष अमेरिका में लगातार और गंभीर सूखा पड़ेगा। अभी जो हालात बन रहे हैं वह कुछ यही इशारा कर रहे हैं। भारतीय संदर्भ में देखें तो इसी बीते जून के अंत से जुलाई के दूसरे पखवाड़े में अब तक उमस और नम हवओं के बीच लू के थपेड़े और भी ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। दरअसल यह वेट बल्ब तापमान वाली जैसी स्थिति होती है जो उमस और गर्मी दोनों से मिलकर बनती है। इसमें तापमान तो 30 डिग्री के आस-पास होता है लेकिन वातावरण में नमीं 90 प्रतिशत होने के बावजूद ऐसे मौसम को सह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वाकई फिलाहाल हालात कुछ ऐसे ही हैं। 2017 का एक अध्ययन बताता है कि, दुनिया न सिर्फगर्म हो रही है बल्कि हवा में नमीं का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है जो यदि तापमान 35 डिग्री वैट बल्ब तक पहुंच जाए तो जिन्दगी के लिए जबरदस्त खतरा भी हो सकता है और बमुश्किल 6 घण्टों में ही मौत संभव है। जहां भारत में समय से पहले आए मानसून की आमद और अब जरूरत के वक्त गफलत ने किसानों सहित आम व खास सबको परेशान कर रखा है। वहीं अमेरिका में भी पारे ने नया रिकॉर्ड बना दिया। कैलीफोर्निया के डेथवैली पार्क में इसी 9 जुलाई को अधिकतम तापमान 54 डिग्री सेल्सयस दर्ज हुआ। इससे पहले 10 जुलाई 1913 को वहां तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो दुनिया में सर्वाधिक है। कैलीफोर्निया, ओरेगन और एरिजोना में तमाम जंगल धधक उठे हैं, धुंआ भरे पायरोकम्युलस बादलों का निर्माण कुछ इस तरह हुआ जो अमूमन जंगलों की बड़ी आग या ज्वालामुखी से बनते हैं। अभी जुलाई के 14 दिनों में ही 2 लाख 45 हजार 472 एकड़ इलाका जलकर खाक हो चुका है। तापमान भी

54 पार कर 57 डिग्री सेल्ससियस पहुंचने पर उतारू है। बिजली गिरने की कई घटनाएं हुईं और आग फैलती चली गई। भारत में राजस्थान का चुरू भी देश का सबसे ज्यादा तापमान वाला शहर बन चुका है। दरअसल यह इंसानों की करतूतों से मौसम का बदलाव है। इस पर 70 विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा किया गया अध्ययन है जिसमें स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। ऐसे प्रभावों को जानने वाला यह पहला और अब तक का सबसे बड़ा शोध है। यह शोध नेचर क्लाइमेट पत्रिका में प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार गर्मी की वजह से होने वाली सभी मौतों का औसतन 37 प्रतिशत कहीं न कहीं सीधे तौर पर इंसानी करतूतों से हुई जिसके लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। इस शोध अध्ययन के लिए 43 देशों में 732 स्थानों से आंकड़े जुटाए गए जो पहली बार गर्मी की वजह से मृत्यु के बढ़ते खतरे में इंसानी करतूतों से जलवायु परिवर्तन के वास्तविक योगदान को दिखाता है। साफहै कि जलवायु परिवर्तन से इंसानों पर दिख रहे खतरे अब ज्यादा दूर नहीं है। जल्द ही मानवीय करतूतों से बढ़ी गर्मी जिसे दूसरे शब्दों में हमारी करतूतों से हुआ जलवायु परिवर्तन भी कह सकते हैं से होने वाली मौतों को जांचने पर यह आंकड़ा हर साल एक लाख के पार पहुंच सकता है।

मान भी लिया जाए कि, 95 प्रतिशत आबादी के पास एयर कंडीशनिंग है या होगी तो मृत्यु दर कम हो सकती है। लेकिन इसे व्यव्हारिक नहीं कह सकते क्योंकि किसान को 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में अपने परिवार के भरण-पोषण करने के लिए बाहर काम करना ही पड़ेगा। दुनिया की प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लेंसेंट का एक अध्ययन तो बेहद चौंकाने वाला है जिसमें केवल भारत में ही हर वर्ष असामान्य गर्मी या ठण्ड से करीब 7.40 लाख लोगों की मौत की चर्चा है। अलग-अलग देखने पर पता चलता है कि भारत में जहां असामान्य ठण्ड से हर वर्ष 6 लाख 55 हजार 400 लोगों की मौत होती तो असामान्य गर्मी से 83 हजार 700 लोग जान गवां बैठते हैं। वहीं मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर की एक टीम ने असामान्य तापमान की वजह से दुनिया भर में 50 लाख लोगों से अधिक की मौत बताकर चौंका दिया है। यह मौत हाल के कोरोना वायरस से हुई मौतों से काफी अधिक है। यह शोध 2000 से 2019 के दौरान का है जिसमें 0.26 सेल्सियस बढ़ा तापमान और मृत्युदर का अध्ययन है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि (आपदा जोखिम न्यूनीकरण) मामी मिजूतोरी भी इस बात को मानती हैं कि, बिगड़ते पर्यवारण से पनपा सूखा अगली ऐसी महामारी बनने जा रहा है जिसके लिए न कोई टीका होगा न दवाई। यानी बिगड़ते पर्यवारण से निपटने की तैयारी और कारगर व्यवस्थाएं ही कुछ कर पाएंगी जिस पर गंभीरता से किसी का ध्यान नहीं है। इसके लिए अभी से तैयारी की जरूरत है। लेकिन क्या कुछ हो रहा है, सामने है। काश! प्रकृति के बिगड़ते संतुलन और धीरे-धीरे बढ़ते तापमान से खुद-ब-खुद मौत के मुंह में समाती दुनिया के बारे में हम, सब कुछ जानकर भी अन्जान होने का स्वांग नहीं करते और कुछ ईमानदार प्रयास कर पाते जो फिलाहाल तो दूर-दूर तक नहीं दिख रहे हैं।

कार्य से ज्यादा कमीशन पर ध्यान नतीजन पंचायत के विकास कार्य राम भरोसे

माही की गूंज, भानपुरा (मंदसौर)। साहिल अगवान

भानपुरा नगर पंचायत द्वारा मूलभूत सुविधा को सुचारू रूप से अंजाम नहीं दिया जा रहा है। नगर में साफ-सफाई, लाइट व पानी की व्यवस्था चरमा गई है। मुख्य नगर परिषद अधिकारी गोविंद पोरवाल द्वारा अपना दायित्व पूर्ण रूप से निर्वाहन नहीं किया जा रहा है। नगर की मूलभूत सुविधाओं से ज्यादा कमीशन के प्रस्ताव पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

बता दें कि, मुख्य नगर परिषद अधिकारी गोविंद पोरवाल अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, पूर्व में भी शामगढ़ पदस्थ के दौरान गोविंद पोरवाल पर कई आरोप लगे थे जिसके बाद एसडीएम द्वारा सीएमओ को निलंबित कर दिया गया था। खैर उस समय मुख्य नगर परिषद अधिकारी गोविंद पोरवाल द्वारा सभी आरोपों को निराधार बताकर राजनीतिक षड्यंत्र बताया गया था। मगर भानपुरा नगर की व्यवस्थाओं को देखते हुए सीएमओ द्वारा उस समय कही गई बात निराधार साबित हो रही है।

कोरोना काल में भी लगे आरोप

कोरोना काल के दौरान मंडल महामंत्री पिंटू पनिहर द्वारा भी सैनिटाइजर की जगह नगर में फिनायल छिडकाव करने का आरोप मुख्य नगर परिषद अधिकारी गोविंद पोरवाल पर लगाया गया था।

पानी की समस्या

नगर के कई क्षेत्रों में पानी भरपूर आता है तो कई जगह पानी का प्रेशर इतना कम है कि, मोटर लगाने के बाद भी उनके दिन भर की पूर्ति नहीं हो पा रही है। पूर्व में भी कई दिनों तक नलों में गंदा पानी आया। अखबारों में खबर प्रकाशित होने के बाद नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई।

अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता नगर भ्रमण

मुख्य नगर परिषद अधिकारी गोविंद पोरवाल द्वारा नगर का भ्रमण भी नहीं किया जाता। वह अपना दायित्व मीटिंग में उपस्थित होना व फाइलों पर साइन करने तक समझते हैं नगर की समस्याओं का समाधान भी शिकायत करने के बाद ही होता है। उनमें भी शिकायतकर्ता पत्रकार या आमजन हो उनकी कई दिनों तक सुनवाई नहीं होती है। जिसके बाद उन्हें छोटी सी समस्या के लिए भी किसी नेता या नगर के किसी जागरूक नागरिक का सहारा लेना पड़ता है।

दुर्घटना को दस्तक देते गड्ढे

पूर्व में नगर परिषद द्वारा रोड के दोनों तरफनाले का निर्माण किया गया था, जो कई जगह से धस कर गड्ढे का रूप ले लिया है जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। नगर की कई दुकानों के बाहर गड्ढे हो रहे हैं मगर फिर भी मुख्य नगर परिषद अधिकारी गोविंद पोरवाल लापरवाह बने हुए हैं।

मुख्य नगर परिषद अधिकारी द्वारा डिवाइडर पर पौधे लगाए गए थे वह भी आधे डिवाइडर पर लगाए गए, गांव के आधे डिवाइडर पर आज भी एक पौधा नहीं लगाए। वही जो पौधे लगाए गए हैं उनमें से भी आधे टेरीगार्ड लगे हैं आधे बिना टेरीगार्ड के ही नगर में देखे जा सकते हैं।

181 पर शिकायत उठाने के लिए बनाते हैं प्रेशर

181 पर शिकायत होने के बाद शिकायतकर्ता की समस्या को हल करने की बजाए, उस पर शिकायत उठाने के लिए प्रेशर किया जाता है। सूत्रों की माने तो जब भी नगर परिषद में उच्च अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की जाती है तो उससे पहले सीएमओ गोविंद पोरवाल या उनके कर्मचारी द्वारा शिकायतकर्ता पर उनकी समस्या का समाधान करें बिना हीं उन्हें शिकायत हटाने के लिए मजबूर किया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

नगर परिषद में भानपुरा पीएम आवास योजना के तहत लोगों को आवास तो मिल रहे है, लेकिन अभी तक उन लोगों को आवास नहीं मिल सके है जिन्हें आवास की सख्त आवश्यकता है। आवास के लिए पात्र हितग्राही कई बार अपने आवेदन जमा कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही अभी तक उनका नाम सूची में शामिल नहीं हो सका है। नगर परिषद क्षेत्र में ऐसे कई लोग है, जिनका संपन्न होने के बाद भी पीएम आवास स्वीकृत हो चुका है। किसी के दूसरी तो किसी को तीसरी किस्त वर्ष भर में भी नहीं डल पाई नगर के कई लोगो ने ब्याज पर पैसा लेकर अपने आवास को पूर्ण किया। पीएम आवास को लेकर कुछ दिन पूर्व नगर परिषद के एक हितग्राही का विडियो भी वायरल हुआ था जिस में एक वर्ष पूर्व आवेदन के बाद भी आवास नहीं मिलने को लेकर हितग्राही कर्मचारियों से लड़ रहा था।

नगर की स्ट्रीट लाइटें

नगर के मुख्य बाजारों, वार्डों, मोहल्ले में स्ट्रीट लाइटें बंद रहने से सड़कों पर अंधेरा रहता है। इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात को दुर्घटनाएं हो रही हैं और साथ ही चोर भी सक्रिय रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका स्ट्रीट लाइटों को ठीक नहीं करवा रही है।

गौरतलब है, नगर में लगी स्ट्रीरट लाइट पिछले कई समय से बंद पड़ी हैं। इस कारण से रात के समय सड़क पर अंधेरा पसरा रहता है। इसके अलावा डिवाइडर पर भी कुछ ही खंबों की स्ट्रीट लाइट चालू हैं, कुछ खंबो की लाइट तो बंद ही रहती हैं। इनके कारण पूरे मार्ग पर अंधेरा पसरा रहता है। इससे लोगों को निकलने में हमेशा डर लगा रहता है। इसी प्रकार झालावाड़ रोड, बोहरा मोहल्ला, लोटखेड़ी रोड, निमथुर गेट, नाई की गली, जटियो के मंदिर के पास, महादेव रोड़, न्यारगर मोहल्ला, वार्ड क्र. 8 सहित अन्य दूसरे स्थानों पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं नगर के लोगों का कहना है कि, लाखों खर्च करने बावजूद शाम होते ही नगर की सड़कों और कई मोहल्लों में अंधेरा पसर जाता है। नगर परिषद हर वर्ष स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस पर लाखों रुपए खर्च करती है। बावजूद शहर में करीब 60 फीसदी स्ट्रीट लाइटें बंद ही रहती हैं। वहीं नगर पंचायत सीएमओ गोविंद पोरवाल जानकारी के बाद भी कुंभकरण की नींद सोए हुए हैं।

गंदगी की वजह से आमजन को गंभीर बीमारियों का खतरा

जिले में अब डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, मंगलवार को सीतामऊ में दो डेंगू पॉजिटिव केस मिले, जिले में चार दिनों में डेंगू के 10 पाजिटिव मामले आ चुके हैं। यह तो सिर्फशासकीय अस्पतालों में पहुंचे मरीजों के आंकड़े हैं, जबकि कई लोग सीधे प्रायवेट अस्पतालों में पहुंचे और वहां पर जांच में डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कागजों में भले ही 10 पॉजिटिव हैं, लेकिन हकीकत में संख्या अधिक है। डेंगू की यह दस्तक खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि पिछले वर्षों में जुलाई के माह में इतनी तेजी से डेंगू कभी नहीं फैला है। ऐसे में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह में जब डेंगू की दस्तक तेज होती है तब हालात अधिक खराब हो सकते हैं।

वहीं नगर परिषद द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है। कस्बे के नाले-नालियों की नियमित सफाई न होने से इनमें गंदगी जमा है। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी की वजह से आमजन को गंभीर बीमारी डेंगू, मलेरिया का खतरा भी सता रहा है। पूर्व में भी कलेक्टर द्वारा सभी नालो की सफाई के निर्देश दिए गए थे। मगर उसके बावजुद भी मुख्य नगर परिषद अधिकारी गोविंद पोरवाल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई व नगर के कई नालों की सफाई नहीं हुई।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा स्पीड ब्रेकर

नगर पंचायत सीएमओ गोविंद पोरवाल द्वारा वाहवाही लूटने के लिए नगर में रेडीमेड स्पीड ब्रेकर लगाए गए थे, जो जिस दिन लगाए उसी दिन से क्षतिग्रस्त होते-होते आज कई जगह स्पीड ब्रेकर का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। सूत्रों की माने तो नीची क्वालिटी के स्पीड ब्रेकर खरीदकर लगाए गए थे। अन्य कई कार्य नगर में हुए हैं जिनके अंदर अच्छी क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

निर्माणाधीन पुल पर हुए हादसे में एक मजदूर की मौत, एक घायल

माही की गूंज, रतलाम।

जिले की जावरा तहसील के ग्राम उपलई में एक निर्माणाधीन पुल पर हुए हादसे में दो मजदूर लोहे के सरियों के नीचे दब गए, दुर्घटना में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रुप से घायल हो गया। बताया जा रहा है, मृतक और घायल आपस में चचेरे भाई थे। मिली जानकारी अनुसार, जावरा से लगभग 8 किमी दूर ग्राम उपलई में बरबोदना भूतेडा टू-लेन सडक का काम चल रहा है, ग्राम उपलई में मन्दिर के समीप इसी मार्ग पर पुलिया निर्माण किया जा रहा है। दोपहर करीब ग्यारह बजे पुलिया निर्माण के लिए लोहे के सरियों को खडा किया जा रहा था कि, अचानक सरियों का जाल नीचे जा गिरा और दो श्रमिक इसके नीचे दब गए। मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने सरिए हटाए और मजदूरों को निकाला। लेकिन तब तक एक श्रमिक नारायण पिता प्रभु दम तोड चुका था, जबकि दूसरा श्रमिक गणेश पिता दीता गंभीर रुप से घायल था। नारायण और गणेश चचेरे भाई है और केलकच्छ तहसिल बाजना के निवासी है। घायल गणेश को गंभीर अवस्था के चलते रतलाम जिला चिकित्सालय रैफर किया गया। नारायण की मौत के मामले में जावरा औधोगिक क्षेत्र पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है।

सामूहिक दुष्कर्म के पांच ओरोपियों को उम्र कैद

माही की गूंज, मंदसौर

जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र की नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के पांच दोषियों को मृत्यु होने तक कैद की सजा सुनाई गई है, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जितेंद्र कुमार बाजोलिया ने मंगलवार को यह सजा सुनाई। वारदात मई 2018 में हुई थी। यह मंदसौर जिले का पहला मामला है, जिसमें नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषियों को मृत्यु होने तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

स्कूल गई नाबालिग का कर लिया था अपहरण

उप संचालक अभियोजन बापू सिंह ठाकुर ने बताया कि, छात्रा 10वीं कक्षा का रिजल्ट लेने स्कूल गई थी लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। तीन दिन बाद 18 मई 2018 को वह गंभीर स्थिति में मंदसौर शहर कोतवाली पहुंची, उसके कपड़े फटे हुए थे। छात्रा ने बताया कि, दशरथ पुत्र प्रभूलाल मोंगिया व फूलसिंह पुत्र शांतिलाल ने उसका अपहरण कर कैलाश पुत्र जगदीश माली, राजू पुत्र दशरथ माली, राहुल पुत्र कन्हैयालाल राठौर को एक वैन में सौंप दिया था। तीनों ने तीन दिन तक खेत में रखकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दशरथ व फूलसिंह को गिरफ्तार किया। कड़ाई से पूछताछ में उन्होंने कैलाश, राहुल एवं राजू का पता बता दिया तो वे भी गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद पीड़िता, पीड़िता के भाई, स्कूल प्राचार्य, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चिकित्सक एवं अनुसंधान अधिकारियों के बयान कोर्ट में हुए। हालांकि, डीएनए रिपोर्ट अभियोजन के पक्ष में नहीं आई, इसके बावजूद अन्य साक्ष्यों व अंतिम बहस में प्रस्तुत किए गए तर्कों के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जितेंद्र कुमार बाजोलिया ने दशरथ, फूलसिंह, कैलाश, राजू और राहुल को मृत्यु होने तक उम्र कैद की सजा सुनाई है।

अंडरब्रीज के पास होगा गौतम आश्रम का निर्माण

माही की गूंज, शुजालपुर।

गुर्जरगौड़ ब्रह्मण समाज के समाजजनों द्वारा दशकों से प्रयासरत महर्षि गौतम आश्रम निर्माण के लिए पुनः एकजुट होकर आश्रम के निर्माण का निर्णय लिया है। महर्षि गौतम आश्रम का बोर्ड अंडरब्रीज के पास मेन रोड पर स्थित निर्माणाधीन स्थल पर लगा दिया गया है जिसका निर्माण कार्य आगामी श्रावण माह में प्रारंभ किया जाएगा।

जिला प्रवक्ता ओम पंचोली ने बताया कि, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यप्रकाश जोशी और प्रांतीय अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी के मार्गदर्शन में समाज अध्यक्ष डॉ. आशीष दुबे और निर्माण समिति अध्यक्ष हरिओम व्यास के नेतृत्व में सभी समाजजनों के सहयोग से निर्माण किया जाएगा। प्रांतीय सहसचिव प्रदीप व्यास ने कहा कि, पंचवटी कॉलोनी मेन रोड पर स्थित निर्माणाधीन स्थल पर ही जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा, क्योकि समाज के पूर्वजो, वरिष्ठों के साथ ही युवाओं की भावनाएं इसी निर्माणाधीन स्थल से जुड़ी हुई है।

उक्त कार्यक्रम में डॉ, आशीष दुबे, प्रकाश जोशी, घनश्याम शर्मा, श्याम उपाध्याय, कपिल व्यास, योगेश शर्मा, रामविलाश त्रिपाठी, प्रमेश त्रिपाठी, आशीष शर्मा आदि उपस्थित थे।

जो हिंदुओं को बांटने कि कोशिश करेगा उसकी खेर नहीं- करणी सेना शक्ति प्रदेश अध्यक्ष

माही की गूंज, शाजापुर।

करणी सेना शक्ति के संस्थापक, अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह डोडिया ने कहा कि, हिन्दुत्व के खिलाफ और देश के खिलाफ जो भी बोलैगा उसकी खेर नही है, भारत देश हर उन भारतीय का है जो देश के साथ है जो देश ओर कानुन के खिलाफ जाएगे ओर आतंकवाद का साथ देंगे वो हर व्यक्ति देशद्रोही है, करणी सेना शक्ति उसके खिलाफहै। योगेन्द्र सिंह डोडिया ने कहा, ओवेसी जैसै के कहने पर जो हिंदुओ को बांटने की कोशिश करेगा उसकी खेर नही है, भारत विश्व गुरु बनेगा हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो साकार होगा। बहुत सारी देशद्रोही ताकत हिंदूओ को बांटने की कोशिश कर रही है। ओवसी जैसे मंद बुंधि को ये नहीं मालूम कि, हिन्दुत्व ओर हिंदुस्तान पर अगर उंगली उठाई तो खेर नही है, करणी सेना शक्ति हर देशभक्त के साथ खड़ी है। करणी सेना शक्ति की मांग है कि, एक देश एक कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए।

दूर की कोड़ी साबित हो सकता है आरओ का पेयजल

माही की गूंज, थांदला

नगर पंचायत परिषद नगर की जनता को सुविधा के नाम पर दुविधा ही दे रही है। परिषद में 14 करोड़ की नवीन नल-जल योजना को स्वीकृत की गई थी, परिषद ने इस योजना के स्वीकृत होकर चालू किए जाने पर नगर की जनता को बड़े जोर शोर से शासन के गुणगान करते हुए शुद्ध आरओ युक्त पेयजल उपलब्ध कराने के सपने भी दिखाए थे जो अब नगर की जनता के लिए दुर की कोड़ी साबित हो रहा है। योजना को संचालित करने वाली एजेंसी न तो योजना का पूर्ण रूप से संचालित कर पा रही है और न ही जनता को आरओ का शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा पा रही है।ऐसी स्थिति में परिषद के जिम्मेदार शुद्ध पेयजल के नाम पर फिजूलखर्च कर चुप्पी साधकर बैठे है।

नगर में आरओ युक्त पानी की जगह अनेक वार्ड मोहल्लों में मटमैला व बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है। विगत एक पखवाड़े से नगर के जवाहर मार्ग लक्ष्मी बेंड वाले मोहल्ले में भी ऐसा ही पानी सप्लाई किया जा रहा है। मोहल्ले वालों के अनुसार इस बारे में नल-जल सप्लाय करने वाले कर्मियों तथा नगर पंचायत में भी जाकर शिकायते की जाने के बावजूद व्यवस्था में सुधार नही किया जा रहा है।

नगर पंचायत के कर्मचारियों के अनुसार उक्त मोहल्ले में पाइप लाइन में खराबी की वजह से यह समस्या आ रही है जिसे ठीक करने हेतु सम्बंधित एजेंसी को अवगत कराया गया है।

एजेंसी नही कर रही अनुबंध का पालन

नल-जल योजना के संचालन का जिम्मा जिस एजेंसी को दिया गया है उक्त एजेंसी न तो व्यवस्थित संचालन कर पा रही है और न अनुबंध अनुसार पालन कर रही है। आये दिन किसी न किसी गली मोहल्लों में गन्दा मटमैला पानी सप्लाई की शिकायत आती है परन्तु उसका त्वरित निदान नही होता है। परिषद के जिम्मेदार भी शिकायत आने पर एजेंसी के कर्मियों को निर्देश देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते है परन्तु पीछे घूमकर नही देखते है कि, व्यवस्था में सुधार हुआ अथवा नही? यही नही अनुबंध अनुसार नागरिकों को नल कनेक्शन देने के बाद उन गड्ढो के रिपेयर की जिम्मेदारी भी सम्बंधित एजेंसी की होती है परन्तु उक्त एजेंसी द्वारा केवल गड्ढे में मिट्टी भरकर इतिश्री की जा रही है।

फिजूलखर्ची

वर्तमान परिषद द्वारा जनता को नल-जल योजना से आरओ वाटर सप्लाय के नाम पर सपने दिखाने के बाद अब बेमौसम में आरओ वॉटर प्याऊ के नाम पर फिर फिजूलखर्च कर जनता के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। गर्मी का पूरा समय निकल गया परन्तु नगर परिषद ने पूरे समय मे कहीं भी सार्वजनिक प्याऊ का संचालन नही किया और न आरओ वॉटर मशीन लगाई गई, परन्तु अब जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तब 8 लाख की लागत से दो आरओ वॉटर मशीनों की खरीदी कर जनधन का दुरुपयोग किया जा रहा है। जन चर्चा अनुसार, परिषद द्वारा यह आरओ वाटर की मशीनें गर्मी के समय लगाई जाती तो राहगीरों व यात्रियों के साथ जनता को इसका लाभ मिलता। ऊंचे दामो पर खरीदी गई इन आरओ वॉटर मशीनों का वर्षाऋतु में आखिर क्या उपयोग होगा? इनकी खरीदी को लेकर भी जनता में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है।

आर्थिक स्थिति कमजोर

नगर परिषद की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होकर दिवालियेपन जैसी है। परिषद पर लम्बे समय से बाजार का लाखो का कर्ज चल रहा है तो शासन स्तर पर भी परिषद करोड़ो के कर्ज में डूबी हुई है, वहीं कर्मचारियों को पगार के लाले पड़ रहे है। स्थाई कर्मचारियों से लेकर सफाई कर्मियों, दैनिक वेतन भोगीयो को कभी भी समय पर वेतन नही मिल पाता है कभी कभी तो दो से तीन माह तक वेतन नही मिलता है। ऐसी स्थिति में भी परिषद की मनमानी, अनियमित्ता, अपव्यय व फिजुलखर्ची नही रुक रही है। अनावश्यक रूप से लाखों की कचरा पेटियां खरीद की जाकर परिषद केम्पस में पड़ी जंग खा रही है। आश्चर्य इस बात का है कि, नगर के हर गली मोहल्लों में प्रतिदिन कचरा वाहन घूमकर घर-घर से कचरा संग्रहित कर रहे है, उसके बाद नगर के जितने चौराहे कचरा पेटियां लगाने के नही है उससे अधिक तादाद में कचरा पेटियां खरीदी कर ली गई।

परिषद के कार्यकाल में खरीदी, स्टोर की जांच व आडिट किसी आईएएस स्तर के ऑडिटर से करवाई जाए तो, बड़े पैमाने पर अनियमित्ता, भ्रष्ट्राचार व जनधन का दुरुपयोग कर फिजूलखर्च सामने आ सकता है।

मंदिर का दो वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया

माही की गूंज, थांदला

सांवरिया सेठ मंदिर पर दो वर्ष के कार्यकाल का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। जिसके अंतर्गत मंदिर के निजी ट्रस्ट का नवीन रजिस्ट्रेशन करवाया गया, बाउंड्री वॉल बनाने की सहमति समाज के लोगों द्वारा ली गई व बाउंड्री वॉल की राशि एकत्रित करने के लिए समाज की एक समिति गठित की गई। साथ ही मंदिर की भूमि का सीमांकन भी किया गया और बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन भी किया गया। मंदिर परिसर में 8 नवीन शौचालय का निर्माण किया गया व मंदिर के सभाकक्ष का रंग-रोगन किया गया।

दुर्घटना में रिटायर शिक्षक की हुई मौत

माही की गूंज, खवासा। रन्नी निवासी रिटायर्ड शिक्षक तेरसिंह पिता रादू कटारा (70) अपने किसी निजी कार्य से खवासा से थांदला की ओर बाइक से जा रहे थे कि, सामने से एक अज्ञात ट्रक तेज गति से आ रहा था, तेरसिंह कटारा की बाइक को जोरदार टक्कर मारकर, ट्रक के साथ चालक रफूचक्कर हो गया। दुर्घटना की सूचना राहगीरों ने खवासा पुलिस चौकी को दी। ट्रक ने टक्कर इतनी जोरदार मारी की दुर्घटना में बाइक चालक शिक्षक तेरसिंह कटारा को सर में गंभीर चोट आने से मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन व चालक की तलाश कर रही है।

सरपंच पति की बल्ले-बल्ले: जमकर कर रहा भ्रष्टाचार

माही की गूंज, शुजालपुर। अजय केवट

ग्राम पंचायत ऊगली जो अपने भ्रष्टाचार संबंधित कार्यों के लिए जनपद पंचायत शुजालपुर में अव्वल दर्जे की श्रेणी में गिनी जाती है। चाहे वह मनरेगा मजदूरी या मस्टर संबंधित मामला हो या खेत तालाब निर्माण संबंधित मामला हो या अन्य ग्रामीण जनहित योजनाओं के संबंधित मामले हो सभी मामलों में सरपंच श्यामाबाई का पति रामनारायण प्रजापति अपनी पत्नी के कंधे पर भ्रष्टाचार की बंदूक को रखकर भ्रष्टाचार की गोलियां चलाने से बाज नहीं आता है। जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा भी सैकड़ों बार जनपद पंचायत शुजालपुर से लेकर जिला पंचायत सीओ तक की जा चुकी है, लेकिन भ्रष्ट व धूर्त सरपंच श्यामाबाई का पति रामनारायण प्रजापति ग्राम पंचायत ऊगली की जनता को मूर्ख बनाकर भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किए जा रहा है। जिसकी शिकायत सोशल वर्कर लक्ष्मीनारायण जाट के द्वारा भी जनपद पंचायत में की जा चुकी है। शिकायत होने के बाद से ही रामनारायण प्रजापति शिकायत को दबाने के लिए जनपद पंचायत के अधिकारियों से गठजोड़ बनाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे है व शिकायत के निराकरण के लिए झूठे प्रतिवेदनो को डाला जा रहा है। भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों को दबाने में ऊगली के सचिव भी कंधे से कंधा मिलाकर इस भ्रष्ट व कर्तव्यहीन सरपंच श्यामाबाई के पति रामनारायण प्रजापति का साथ दिए जा रहा है। भ्रष्टाचार का यह खेल इन तीनों तिकड़ियों द्वारा पिछले विगत वर्षों से खेला जा रहा है, जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत के लोगों को आज तक नहीं है।

पिछले विगत वर्षों के कार्यकाल में सरपंच श्यामाबाई के पति द्वारा कई फर्जी बिलों को लगाकर, वहां फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करके जनहित के लिए आई हुई लाखों रुपए की राशि को निकाल ली गई। यह सारा खेल सचिव के साथ रामनारायण प्रजापति अपनी पत्नी के पद का दुरुपयोग करके किए जा रहे हैं।

सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत।

राष्ट्रीय सलाहकार ने डूब प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

माही की गूंज, अलीराजपुर

आदिवासी विकास मोर्चा द्वारा गत दिवस जिले की सोंडवा तहसील के डूब प्रभावित गांव अंजनबारा में डूब प्रभावित ग्रामीणों के साथ चर्चा कर शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, जैविक खेती, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एवं सरकारी योजना में लाभान्वित होने में आ रही दिक्कतों संबंधी समस्या का हल करने के लिए चर्चा की। आदिवासी विकास मोर्चा के राष्ट्रीय सलाहकार भंगूसिंह रावत ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ समस्याएं जानी। इस दौरान ग्रामीणों को बोट के लिए डीजल की समस्या थी तो उन्होने आश्वासन दिया कि, मोर्चा के द्वारा डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होने गांव के सभी बच्चों की सूची बनाई जाए एवं उन सभी को कॉपी, किताब एवं एक अस्थाई शिक्षक के साथ अस्थाई स्कूल भी खोलने को लेकर सहमति बनाई। साथ ही यह देखा गया कि, बालिका शिक्षा का प्रतिशत जीरो है। इस स्कूल में बालिका शिक्षा को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस नाव वाली चलती है उसी प्रकार अन्य विभागों की कॉमन एंबुलेंस इन गांव में चलाने को लेकर मोर्चा के द्वारा उच्च स्तरीय बातचीत की जाएगी ताकि शासन की जो अन्य योजनाएं हैं वह भी इन्हें मिल सके। पानी की विशेष समस्या को हल करने के लिए भी विशेषज्ञों का सहयोग लेकर प्लानिंग बनाने को लेकर सहमति हुई है। इसके अतिरिक्त स्वर्गीय अनील माधव दवे के माध्यम से संचालित बोट मेडिकल उपचार के लिये माँ नर्मदा के किनारों पर बसे लोगो को दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। बोट पर डॉक्टर कमलेश भावसार ओर दिनेश सोलंकी से विस्तार से बातचीत हुई है कि हम मिलजुलकर इस स्वास्थ्य सेवा को कैसे और बेहतर करे।

52 सेंपल चलित वाहन ने जाँचे

माही की गूंज, खरगोन

जिले के मण्डलेश्वर और महेश्वर क्षेत्र में बुधवार को खाद्य चलित प्रयोगशाला पहुँची। यहां खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थों के सेंपल लेकर जॉचे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एचएल अवास्या ने जानकारी देते हुए बताया कि, 52 सेंपल में से 3 सेंपल अमानक पाए गए। इसमें महेश्वर की श्रीहरि केंटिन से सोयाबीन तेल जॉचा गया जो जांच में फेल हुआ। मौके पर ही 7 लिटर सोयाबीन का तेल नष्ट किया गया। संचालक को नोटिस भी जारी किया गया। इसके अलावा महेश्वर के ही श्री शरणम् होटल से तुवर दाल का सेंपल लिया गया था जो जांच में फेल हुआ। इसी तरह मण्डलेश्वर के शेर-ऐ-पंजाब होटल से मूंगफ्ली तेल का सेंपल जांचा गया। प्राथमिक रूप से जांच करने पर तुवर दाल और मूंगफ्ली का तेल अमानक साबित हुए है। इन दोनों के सेंपल भोपाल जांच के लिए भेजे जाएंगे। चलित खाद्य प्रयोगशाला में अर्पित अग्रवाल ने अपने घर के घी का भी सेंपल जांच करवाया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अवास्या ने बताया कि, जांच के दौरान मावा, जलेबी, मिल्क, केक, पनीर, दही, मसाले और दालों के अलावा कई खाद्य सामग्रीयों के कुल 52 सेंपल लिए गए। इस कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरसिंह सोलंकी और केमिस्ट नीरज भी मौजूद रहे। आज खाद्य चलित वाहन प्रयोगशाला बड़वाह में सेंपल जांच करेगी।

टूरिज्म डायरेक्टर ने तलाशी महेश्वर के गांवों में पर्यटन की संभावनाएं

माही की गूंज, खरगोन

म.प्र. टूरिज्म बोर्ड के डायरेक्टर डॉ. मनोज कुमार सिंह महेश्वर के आस-पास के गांवों में अपने दल के साथ पहुँचे। यहां उन्होंने पर्यटन नगरी महेश्वर के आस-पास लाड़वी, केरियाखेड़ी और मातमुर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचकर ग्रामीणों से पर्यटन संभावनाओं के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों को पर्यटन विकास में जोड़ने के दृष्टि से अवलोकन किया। ग्रामीणों से चर्चा के दौरान होमस्टे पंजीयन, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे महत्वपूर्ण बिंदूओं पर चर्चा की। इस दौरान पर्यटन बोर्ड के एडवॉयजर अमितसिंह, स्कील डेवलपर प्रशांत छिरोलिया और स्वाति प्रमर ने भी ग्रामीणों से पर्यटन से संबंधित बिंदूओं पर जानकारी ली। पर्यटन विभाग के नोडल नीरज अमझेरे ने बतया कि, आज कलेक्टर अनुग्रहा पी. की मौजूदगी में एडवेंचर वार्टर स्पोर्टस इवेंट और प्रमोशन के संबंध में पर्यटन विभाग की नर्मदा रिट्रिट में बैठक आयोजित होगी। स्थानीय अधिकारियों में एसडीएम मिलिंद ढोके, तहसीलदार सोनकर मौजूद रहे।

शिखर खेल पुरस्कार के लिए 31 तक आवेदन आमंत्रित

माही की गूंज, बड़वानी। शिखर खेल अलंकरण पुरस्कार एकलव्य, विक्रम विश्वामित्र, लाईफ टाईम अचीवमेंट एवं स्व.श्री प्रभात जोशी खेल पुरस्कार प्रदान करने हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग की वेब साइट इेलूउचण्हवअण्पद पर ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 जुलाई तक रहेगी। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त पुरस्कारों के लिये ऑनलाइन आवेदन अन्तिम तिथि तक ही मान्य होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त ऑनलाइन जनरेट होने वाली पावती या स्लीप के साथ आवेदन में उल्लेखित जानकारी, खेल उपलब्धियों के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न कर अन्तिम तिथि 31 जुलाई तक जिला खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय में कार्यालयीन समय में आवश्यक रूप से जमा करवा सकते हैं।

आशाग्राम पहाड़ी पर प्रारंभ हुआ बगीचे का निमार्ण, स्वयं सेवकों ने किया श्रमदान

माही की गूंज, बड़वानी

मुख्यमंत्री के अंकुर अभियान के तहत आशाग्राम की पहाड़ी पर बड़े पैमाने पर होने वाले पौधारोपण एवं पर्यटको की दृष्टि से विभिन्न निर्माण कार्य जनसहयोग से निरन्तर जारी है। बुधवार को कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा के निर्देशन में आशाग्राम पहाड़ी पर्यावरण सहजो समिति के स्वयं सेवको ने बगीचे का निर्माण प्रारंभ कर उसमें विभिन्न फूलो के पौधो का रोपण किया है। जिसके कारण हनुमान के सामने की पहाड़ी की रंगत देखते ही देखते निखर गई है। इस श्रमदान के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा एवं एसडीएम बड़वानी घनश्याम धनगर की उपस्थिति में स्वयं सेवको ने लगभग 3 सौ से अधिक विभिन्न फूलो एवं सौभायमान पौधो का रोपण किया है। वहीं निर्मित होने वाली गोवर्धन पहाड़ी के निर्माण में भी श्रमदान कर बनने वाले कुण्ड का आकार निश्चित किया है। उल्लेखनीय है कि, शहर के मध्य स्थित इस 33 एकड़ की विशाल पहाड़ी पर लगभग 20 हजार विभिन्न पौधो के रोपण की तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। इसके तहत बड़े पैमाने पर बॉस, नीम, पीपल, बड़, करंज, चिरौल, आवला सहित अन्य पौधो का रोपण किया जाएगा। वहीं पहाड़ी पर दो पाथवे, दो पक्षी विहार हट, गोवर्धन पहाड़ी एवं कुण्ड, आदियोगी की विशाल मूर्ति एवं विभिन्न बगीचों का निर्माण कार्य प्रारंभ है।

रफ्ता-रफ्ता बढ़ती जा रही है टीकाकरण करवाने वालों लोगों की रफ्तार

जिले में 3 लाख से अधिक लोग करवा चुके है अपना वैक्सीनेशन

माही की गूंज, बड़वानी

जिले में वैक्सीनेशन को लेकर फैला धुंध हट गया है, तथाकथित कुछ लोगो की अफ्वाह को परे करते हुये अब जिले में टीकाकरण करवाने वालो की संख्या दिनो-दिन बढ़ती ही जा रही है। इसके लिये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सामान्य रूप से उत्साह देखा जा रहा है, टीकाकरण केन्द्रों पर प्रातः 9 बजे के पूर्व ही लम्बी-लम्बी लाइने लग जाने के कारण अधिकांश टीकाकरण केन्द्रों पर दोपहर तक ही आवंटित लक्ष्य पूर्ण हो रहा है। इसके मददेनजर जिले के कोरोना प्रभारी मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों से चर्चाकर जिले को एक लाख वैक्सीन का डोज दिलवाने की बात कही है।

कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिता सिंगारे ने बताया कि, बुधवार तक जिले में 3 लाख 19 हजार 606 लोग अपना वैक्सीनेशन करवा चुके है। इसमें 2 लाख 73 हजार 537 लोगों को प्रथम डोज एवं 46 हजार 69 लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। उन्होने बताया कि हेल्थ वर्कर के तहत 12 हजार 578 लोगों का, फ्रंट लाईन वर्कर के तहत 9 हजार 260 लोगों का, 18 से 44 वर्ष की आयु के 1 लाख 64 हजार 771 लोगों का, 45 से 59 वर्ष की आयु के 81 हजार 366 लोगों का, 60 वर्ष से अधिक आयु के 51 हजार 631 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जो निर्धारित लक्ष्य 918900 का 34.78 प्रतिशत है। इसमें 18 प्लस के लोगो का 26.16 प्रतिशत एवं 45 प्लस का 53.57 प्रतिशत योगदान है।

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं निति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष का दौरा कार्यक्रम

माही की गूंज, बड़वानी। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं निति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री सचिन चतुर्वेदी 22 जुलाई को जिले के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। वहीं जिला मुख्यालय पर अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान उनके साथ विभिन्न विशेषज्ञ एवं भोपाल से आये उच्च अधिकारी भी रहेंगे।

कलेक्टरेट कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार सचिन चतुर्वेदी 22 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे से कलेक्टरेट कार्यालय बड़वानी में अधिकारियों, जन अभियान परिषद के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। तत्पश्चात वे तेजस्विनी महिला सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन व निमाड़ महिला एफ्पीओ से रबि फसल के समर्थन मूल्य पर उपार्जन संबंधित चर्चाकर जानकारी प्राप्त करेंगे।

श्री चतुर्वेदी इसी दिन दोपहर 2.15 बजे तलवाड़ाबुजुर्ग में गठित नेचर टू अर्थ कृषि विकास बीओडी व किसानों एवं पंचायत के पदाधिकारियों से चर्चा, दोपहर 3 बजे चकेरी में वनधन योजनान्तर्गत भारत पेट्रोलियम ट्रायफेड सीएसआर अंतर्गत स्वसहायता समूहो को हेण्डलुम प्रशिक्षण का निरीक्षण एवं चर्चा करेंगे। इसी प्रकार श्री चतुर्वेदी इसी दिन दोपहर 3.40 बजे हरिबड़ में स्थित मशाला यूनिट का अवलोकन व संचालको से चर्चा उपरान्त सायं 4.30 बजे ठीकरी पहुंचकर वहाँ संचालित आजीविका केन्द्र का अवलोकन एवं सीएलएफ पदाधिकारियों से चर्चा के उपरान्त धार के लिये प्रस्थान करेंगे।

लोकसभा सांसद ने केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्री से की मुलाकात

माही की गूंज, बड़वानी

क्षेत्र के लोकसभा सांसद गजेन्द्रसिंह पटेल ने केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा से उनके दिल्ली निवास पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव के नेतृत्व में मुलाकात की एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वन अधिकार के पट्टे के लिए जो कानून पास किया गया, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे जनजाति समूह के लिए अत्यन्त उपयोगी बताया। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री अशोक नेतेजी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री जसमीत कौर के साथ भी जनजातीय विषय पर विस्तृत चर्चा की। सांसद गजेन्द्रसिंह पटेल ने बताया कि, जमीनी स्तर पर जिले के जनजातीय समुदाय को इस कानून का लाभ मिले। इसके लिए व्यापक स्तर पर योजना बनाकर जनजाग्रति का कार्य किया जाएगा।

जनजातीय विभागीय विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा 31 जुलाई को

माही की गूंज, बड़वानी

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बड़वानी निलेश रघुवंशी से प्राप्त जानकारी अनुसार सह सचिव मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेजिडेंशियल अकैडमी सोसायटी भोपाल के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु विभागीय परिशिष्ट विद्यालयों में कक्षा 6वीं एवं 9वी में प्रवेश परीक्षा 31 जुलाई को दो पालियों में (कक्षा 6वी हेतु प्रातः 10.30 से 12.30 बजे एवं कक्षा 9वी हेतु दोपहर 2.30 से 4.30 तक) आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि, बड़वानी जिले में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी, पाटी, राजपुर, ठीकरी, सेंधवा, निवाली, पानसेमल, शासकीय एकलव्य आवासीय विद्यालय बड़वानी एवं सेंधवा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेंधवा, पानसेमल, निवाली, ठीकरी, राजपुर, पाटी, बड़वानी, शासकीय बालक हाईस्कूल राजपुर, निवाली, पाटी, पानसेमल, सेंधवा, बड़वानी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 बड़वानी में परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होने बताया कि, इन केन्द्रो पर 6 हजार 751 परीक्षार्थियो ने परीक्षा देने हेतु अपना पंजीयन करवाया है। इसमें कक्षा 6टी हेतु 4 हजार 107 परीक्षार्थी एवं कक्षा 9वी हेतु 2 हजार 644 परीक्षार्थी सम्मिलित है।

हर्षोल्लास के साथ मनाया ईद-उल-अजहा का त्यौहार

माही की गूंज, खरगोन

जिले में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का पर्व मुस्लिम समाजजनों ने हर्षोल्लास से मनाया। हजरत इब्राहीम अलेहिस्लाम से अल्लाह ने लिए इम्तहान की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। कोरोना संक्रमण के चलते शासन की गाईड़लाइन अनुसार शहर की दोनों ईदगाह पर मात्र 6-6 लोगो द्वारा ईद उल-अजहा की विशेष नमाज पढ़ी गई। कोरोना के चलते दो गज दूरी, मास्क जरूरी का पालन करते हुए डिजिटल तरीके से मोबाइल संदेश, व्हाट्सएप्प, वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे को ईद की मुबारक़बाद देकर खुशियों को साझा किया। अनवर जिन्द्रान ने बताया कि, यह भी दिलचस्प बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईद-उल-अजहा को कहीं भी बकरीद नहीं कहा जाता। ईदगाह मैदान पर लगने वाला मिनी मेला भी नही लगा जिस कारण छोटे बच्चो में मायूसी जरूर रही लेकिन कोरोना के प्रति सजगता भी नज़र आई। समाजजनों ने अपने घरों पर ही ईद की नमाज अता कर कोरोना वबा (महामारी) से मुक्ति और अच्छी बारिश के साथ खुशहाली, अमन शांति की दुआएं मांगी। नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया जिसे गरीबो, रिश्तेदारों में बांटकर ईद की खुशियां मनाई गई। ईद के पर्व को जिलेभर में शांति और सद्भाव के साथ मनाया गया।

कोरोना का हो खात्मा, मुल्क में बना रहे अमन-चैन

अकीदत के साथ मना ईद-उल-अजहा घरों में अदा की गई नमाज

माही की गूंज, अलीराजपुर

ईद-उल-अजहा के मौके पर मुस्लिम बस्तियों में सुबह से रौनक देखी जा रही थी। लोगों ने सुबह जल्दी उठकर कुर्बानी के लिए जानवरों को नहला-धुलाकर तैयार कर दिया। कुर्बानी के जानवरों को मीठा खिलाया गया। जानवरों को तैयार करने के बाद खुद तैयार होकर कोविड-19 गाईडलाइन के तहत घरों में ही ईद की नमाज अदा की गई।

ईद की नमाज में नौजवानों, बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गो ने पाक परवरदिगार से देश की तरक्की के साथ ही देश में आपसी भाईचारे व जानलेवा कोरोना को खत्म करने की दुआ मांगी। वहीं लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। न की राह में अकीदत और यकीन के साथ सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना से जुड़ा ईद-उल-अजहा का त्यौहार को परम्परागत अकीदत और खुशी के माहौल में मुस्लिम परिवारों द्वारा ईद-उल-अजहा के रूप में मनाया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुस्लिम समाज द्वारा अपने घरों पर ही नमाज अदा की गई, इस बार ईद की रौनक गायब रही।

ईदुज्जुहा की नमाज में सभी ने अल्लाह से यह दुआ की कि, दुनिया मे जो महामारी फैली हुई है उससे निजात मिले और भारत में अमन चैन और भाईचारा बना रहे। हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर हो ये ही दुआओं के साथ सभी ने ईद-उल-अजहा की नमाज अदा की।

बच्चों में दिखा उत्साह-ईद को लेकर बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया। ईदी के रूप में मिलने वालें पैसे व उपहार को लेकर बच्चे काफी खुश नजर आए। इस दौरान बच्चें गली मुहल्लों में घुमते व खेलते नजर आए।

साथिया का शत प्रतिशत कोविड टीकाकरण किया गया

माही की गूंज, अलीराजपुर।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीकाकरण अधिकारी और आदिवासी चेतना शिक्षण सेवा समिति के मार्गदर्शन में जिले के समस्त साथिया का कोविड-19 वैक्सीनेशन करवाया गया, अब साथिया के द्वारा बिग्रेड सदस्यों का भी टीकाकरण करवाया जा रहा है। जिले में साथिया के द्वारा ब्रिग्रेड सदस्यों का भी शत प्रतिशत टीकाकरण करवाने हेतु प्रयास किया जा रहे है। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला समन्वयक भूपेंद्र मंडलोई, परियोजना समन्वयक शाकिर खान, परामर्शदाता हिना मकरानी, प्रशिक्षक संजय सोलंकी, मंजू किराड़, साहिल खान, सुनीता किराड़ का सहयोग रहा।

भीड़-भाड़ भरे बाजार व बस स्टैंड पर स्थित दुकान से गल्ला चोरी

माही की गूंज, आम्बुआ।

बस स्टैंड के समीप स्थित अनाज की दुकान से नोटों से भरा गल्ला चोरी हो गया। जिस समय गल्ला चोरी हुआ दुकान के आस-पास भीड़ थी मगर किसी ने चोर को नहीं देखा, पुलिस थाने पर चौरी की मौखिक सूचना दी गई है।

अनाज व्यापारी हासीम अली बोहरा ने बताया कि, आज हाट बाजार का दिन होने से उन्होंने गल्ला (पेटी) में 30-35 हजार रूपए रखें तथा माल खरीदने हेतु ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, इसी बीच कुछ मिनट के लिए वह गल्ले के पास से उठकर दुकान के चबूतरे के एक कोने तक गए, इसी बीच कोई अज्ञात चोर गल्ला (पेटी) उठाकर रफूचक्कर हो गया। घटना के मौखिक सूचना आम्बुआ थाने पर दी गई। घटना की खबर लगते ही दुकानदारों में दहशत व्याप्त है। बता दे कि, दुकान बस स्टैंड के समीप है तथा स्थान चहल-पहल भरा है, इसके बावजूद जरा सी चूक होते ही इतनी बड़ी वारदात हो जाने से सभी स्तब्ध है।

अ.जा. और अ.ज.जा. वर्गों के कर्मचारियों पर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्गो के कर्मचारियों पर भेदभाव एवं अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरोध में कलेक्टर सुरभि गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर पटवारी नितेश अलावा के बहाली की मांग की। कांग्रेसियों ने चतावनी देते हुए कहा कि, पटवारी अलावा की बहाली आगामी दिनो मे नही हुई तो जिला कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन एवं धरना-प्रर्दशन करेंगी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल, विधायक मुकेश पटेल, पुर्व विधायक सुलोचना रावत सहित सभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

आदिवासी कर्मचारियों पर कार्रवाई बंद हो-कांग्रेस के नेता एवं पदाधिकारीगण ओर कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय पर जमा हुए। यहां से जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल, एवं विधायक मुकेश पटेल के नेत्रत्व मे कार्यकर्ता कलेक्टोरेट कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसी नेताओ ने अनुसूचित जाति-जनजाति वर्गो के कर्मचारियों पर कार्रवाई के विरोध मे शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी नेताओ ने ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन मे बताया कि, म.प्र. में अनुचित जाति-जनजाति बाहुल क्षेत्रों अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, इंदौर आदि जिलों में पिछले एक वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति-जनजाति वर्गो कर्मचारियों तथा अन्य लोगों पर भेदभाव एवं अन्यायपुर्ण कार्रवाई भाजपा सरकार के ईशारो पर की जा रही है, जिसकी कांग्रेस घोर निंदा करती है। भाजपा सरकार में दलित, शोषित एवं पीडित आदिवासियों के हित में बोलना ओर उनकी लडाई लडना एक प्रकार से गुनाह हो गया है। नेमावर मे आरोपियों ने आदिवासी समुदाय की लड़की का बलात्कर कर हत्या कर परिवार सहित पांच लोगों को मारकर 10 फिट गहरे गड्ढे में दफ्न कर दिया। राजनीतिक दवाब ओर संरक्षण के कारण अपराधी खुल्लेआम घूम रहे है, इस घटना की जांच सीबीआई से हो ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मील सके। जोबट हल्का क्षैत्र के पटवारी नितेश अलावा ने नेमावर बलात्कार हत्याकांड सहित अन्य क्षैत्रो की घटनाओ का विरोध दर्ज किया था। जिसे राजनेतिक दबाव मे आकर जोबट एसडीएम शयामवीरसिंह नरवरिया ने बिना कोई नोटिस दिए पटवारी अलावा को निलंबित कर दिया। आदिवासी ओर दलितों वर्गो के लोगों पर पुलिस ओर प्रशासन द्वारा झूठे ओर फर्जी मुकदमे में कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। आदिवासियों की जमीन पर अवैध खरीद फरोख्त के काले खेल पर रोक लगाया जाए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने कई मुददो पर ज्ञापन सोपा।

इस अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष ओमप्रकाश राठौर, अलीराजपुर ब्लॉंक कांग्रेस अध्यक्ष केलाश चैहान, आजाद नगर ब्लॉंक कांग्रेस अध्यक्ष लईक मोहम्मद शैख, जोबट ब्लॉंक कांग्रेस अध्यक्ष भुरु अजनार, कठिवाडा ब्लॉंक कांग्रेस अध्यक्ष पारसिंह बारिया, सौण्डवा ब्लॉंक कांग्रेस अध्यक्ष मोहनसिंह निंगवाल, छकतला ब्लॉंक कांग्रेस अध्यक्ष उशानसिंह गरासिया, उदयगढ के कमरु अजनार, ज्ञानसिंह मुजाल्दा, तरुण मंडलोई, सुरेश सारडा, सानी मकरानी सहित अन्य कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता मोजुद थे।

पंचायत स्तर से लेकर आगे के सभी चुनाव हमें जीतना है- श्री जोशी

माही की गूंज, आम्बुआ।

आगामी चुनाव जो कि जोबट विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के रूप में होना है, उसकी तैयारी बूथ स्तर पर होगी तभी हम जीत हासिल कर सकेंगे। इस बार संगठित होकर चुनाव लड़ना होगा, कार्यकर्ताओं को यह समझना होगा कि, उन्हें आगामी समय में पंचायत स्तर से लेकर आगे के सभी चुनाव जीतना है। उक्त बात आम्बुआ में कृषि उपज मंडी प्रांगण में जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र जोबट की विधायक सुश्री कलावती भूरिया के निधन से रिक्त हुई सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा करते हुए खरगोन क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक तथा अलीराजपुर जिले पर्यवेक्षक रवि जोशी ने कही। उन्होंने आगे कहा कि, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संगठित होना जरूरी है, बूथ स्तर तक हम कार्यकर्ताओं को लगाएं तथा पूर्ण मन से कार्य करें। मैं यहां टिकट बांटने नहीं आया हूं टिकट मांगने का अधिकार सभी को है मिलेगा किसी एक को, जिसे मिले उसे पूरा सहयोग कर पार्टी को जीत दिलाने हेतु सभी संकल्प लें। कार्यक्रम में स्वागत भाषण अजमेर सिंह रावत ने दिया उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में ग्रामीण कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इनके बाद अमान पठान, भुरू अजनार, कमरू अजनार, हरीश भाबर, ज्ञानसिंग मुजाल्दा, दीपक भूरिया, मोनू बाबा, विशाल रावत, श्रीमती सुलोचना रावत (पूर्व विधायक) के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल ने अपने उदबोधन में स्व. कलावती भूरिया के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके अधूरे रह गए कार्यों को पूर्ण करने हेतु कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का आव्हान किया। अलीराजपुर विधायक मुकेश पटेल ने कहा कि, जोबट विधानसभा क्षेत्र को अनाथ न समझे, मैं तथा जिलाध्यक्ष और पूरा पटेल परिवार जोबट विधानसभा के नागरिकों के साथ है, हम विकास रुकने नहीं देंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में रवि जोशी को साफा, झुलडी पहनाकर तथा तीर कमान भेटकर महेश पटेल, मुकेश पटेल तथा दीपक भूरिया ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। विकासखंड जोबट, उदयगढ़, आजाद नगर, कट्ठीवाड़ा तथा अलीराजपुर से आए ब्लॉक अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने हार माला पहनाकर श्री जोशी का स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व सेवादल अध्यक्ष राजेंद्र गेहलोत, पारसी बारिया, नारायण भाई, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर, लइक मोहम्मद, कमल सिंह कनेश, सवैसिंह तोमर, महेन्द्रसिंह रावत, रमेश भाई, मोगली खान, अनिल डावर आदि अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश राठौड़ ने किया।

कृषि विस्तार अधिकारी के अभाव में कृषक परेशान

माही की गूंज, आम्बुआ। मयंक अग्रवाल

ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों के मार्गदर्शन आदि के लिए कृषि विभाग बनाया गया है। इस विभाग के कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हुए उन्हें शासन की विभिन्न लाभदायक योजनाओं का लाभ प्रदान कराते हैं, यदि इन कर्मचारी का अभाव हो तो कृषकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। वर्तमान में यही स्थिति आम्बुआ सहित आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई है, जहां कृषक परेशान हो रहे हैं और शासन-प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है।

शासन कृषि को लाभ का धंधा बनाने की रोज घोषणाएं करता है, लेकिन क्या कृषि लाभ का धंधा बन सकती है या भविष्य में बनेगी? यह भविष्य के गर्त में है। कृषि संबंधित विभाग ही जब उदासीन हो तो कृषि और कृषक कैसे उन्नति करेंगे, यह विचारणीय है।

जिसकी नियुक्ति हुई उसने यहां आने से मना कर दिया

आम्बुआ क्षेत्र में कार्यरत कृषि विस्तार अधिकारी जो जिला मुख्यालय से आना-जाना करते थे, विगत महीनों कोरोना महामारी के दौरान काल का ग्रास बन गए। कृषि विस्तार अधिकारी स्व.श्री बोडेले समय-असमय आम्बुआ आकर कृषकों को खाद-बीज, दवा, कृषि उपकरण आदि जो भी शासन की लाभप्रद योजनाएं होती है थी वे उन्हें उपलब्ध कराते रहते थे। उनके निधन के दो-तीन माह बाद भी उनके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी की नियुक्ति विभाग ने की है। इस बाबत् जब जिले के कृषि विभाग से चाही गई तो विभाग में पदस्थ आदेश अचाले ने बताया कि, आम्बुआ तथा आस-पास के क्षेत्र हेतु श्री बघेल को चार्ज दिया गया है। इधर श्री बघेल क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहे है। क्षेत्र में कृषि कार्य भी इस मौसम का लगभग पूर्ण होने जा रहा है और कृषकों को न तो बीज मिला न ही खाद और न ही कृषि उपकरण जैसे हल, बक्खर, आदि भी नहीं मिले। गूंज प्रतिनिधि ने जब दूरभाष पर श्री बघेल से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि, वे जहां कार्य कर रहे हैं उस कार्य स्थल (फील्ड) से आम्बुआ क्षेत्र लगभग 20 किलोमीटर दूर होने से वे अपने वर्तमान कार्य क्षेत्र से बाहर इतनी दूर नहीं जा सकते और न ही कृषकों से मुख्यालय पर संपर्क बना सकते हैं, इस कारण उन्होंने विभाग को लिखकर दे दिया है कि, वे वहां कार्य नहीं कर सकते हैं तथा किसी अन्य की नियुक्ति (चार्ज) की जाए। अब देखना यह है कि, किस विभागीय कर्मचारी को आम्बुआ क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी का चार्ज दिया जाता है या पूरा के पूरा बरसात का मौसम (खरीफ) युं ही कृषकों को परेशानी के साथ गुजारना पड़ेगा।

उज्जैन पुलिस आई वाहन चोर पकड़ने, पेटलावद पुलिस के पास मामला दर्ज करने की फुर्सत नही

ऑनलाइन बिकने आई गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव के नाम पर उड़ा लेते हैं शातिर बदमाश

माही की गूंज, पेटलावद।

वाहनों की अच्छी कीमत की चाह में वाहन मालिक अपने वाहन को पूरी जानकारी और पते के साथ ऑनलाइन वेब साइड पर डाल देते हैं, ताकि खरीदार वाहन के लिए सीधे वाहन मालिक से संपर्क कर ले और अच्छी कीमत पर वाहन की बिक्री हो जाए। ऐसी पोस्ट को ताक में न केवल खरीदार रहते हैं बल्कि धोखाधड़ी करने वाले भी ताक में रहते हैं जो योजनाबद्ध तरीके के अपने काम को अंजाम देकर निकल जाते हैं। वही ऐसे शातिर बदमाश अपने पीछे पर्याप्त सबूत छोड़ने के बाद भी पुलिस ऐसे शातिर तरीके से अंजाम दिए अपराधों पर लगाम नही लगा पाती है और न ही अपराध दर्ज करती है। ऐसी ही एक घटना पेटलावद में 30 जून को अंजाम दी गई, जब ऑनलाइन वाहन खरीदने के लिए आए युवक ने वाहन की टेस्ट ड्राइव लेने का बोलकर वाहन लेकर फरार हो गया।

धोखे से चोरी किया गया वाहन।

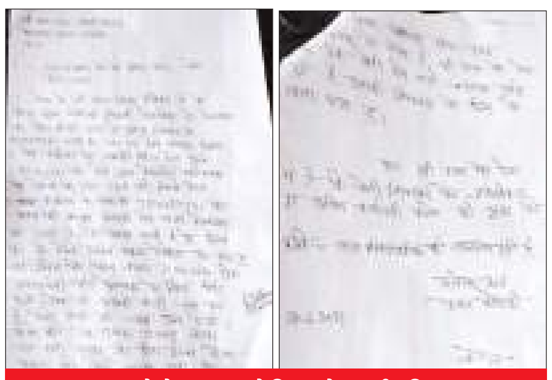

थाने में 30 जून को दिए आवेदन की प्रति।

सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत।

थाने में मोबाइल नंबर सहित दिया आवेदन, अब तक मामला नही हुआ दर्ज

अपने साथ हुई धोखाधड़ी या कहे लुट, की शिकायत कमल पिता सुरेश सोलंकी निवासी मोहनकोट ने पेटलावद थाने में दर्ज करवाई। कमल सोलंकी ने बताया कि, उसका निजी दुपहिया वाहन कीमत लगभग 2 लाख रुपए का होकर वाहन क्रमांक एमपी 09 वीएच 9781 शशांक गुप्ता से खरीदा था। उक्त वाहन को बेचने के लिए मैंने मोबाइल एप्लीकेशन डाली थी, जिसको देखकर क्रेता बने व्यक्ति ने अपना नाम भगवान बताकर मोबाइल नम्बर 7241137741 से कॉल कर कहा कि, मुझे आपका वाहन खरीदना है और वाहन की उचित कीमत लेकर आ रहा हुं। सौदे के उद्देश्य से दोनों पक्ष पेटलावद के श्रद्धांजलि चोराहे पर मिले, मुंह पर मास्क पहने व्यक्ति ने वाहन का सौदा करते हुए वाहन की टेस्ट ड्राइव लेने का बोल कर चाबी ली और वाहन चलाकर देखने के नाम पर वाहन ले गया। काफी देर बाद भी वापस नही आने पर फोन लगाया तो फोन भी बन्द आया। जिसके बाद मेरे साथ हुई लुट का अहसास हुआ ओर रिपोर्ट पेटलावद थाने में लिखवाई।

नही हुआ मामला दर्ज, मोबाइल लोकेशन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के हाथ खाली

आवेदन रखकर पेटलावद पुलिस ने लूट का शिकार हुए कमल सोलंकी को आश्वस्त किया, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी न तो मामला दर्ज हुआ और न ही रिपोर्ट दर्ज हुई। मामले की शिकायत कलम सोलंकी द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर की गई, जिसके बाद पेटलावद पुलिस ने कमल को थाने पर बुलाकर दोबारा आश्वासत कीया कि, हमने मोबाइल नम्बर ट्रेस कर लिया है जो हरदा का बताया जा रहा है, उक्त मोबाइल लोकेशन के अनुसार पुलिस की टीम चोर को पकड़ने जाएगी। लुट के शिकार युवक ने पुलिस से मिले आश्वासन ओर जानकारी के झांसे में आकर सीएम हेल्पलाइन से शिकायत हटवा दी। तब से लेकर अब तक पुलिस ने न तो मामला दर्ज किया न ही उनके बताए अनुसार हरदा के लिए टीम भेजकर जांच करने की कोई जानकारी नही दी। वाहन मालिक आज भी एफआईआर के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है।

उज्जैन पुलिस ने बामनिया से पकड़े इस प्रकार की वारदात के आरोपी

मिली जानकारी अनुसार कुछ दिन पूर्व उज्जैन पुलिस द्वारा पेटलावद थाने की ही बामनिया चौकी क्षेत्र से दो लोगो को इस प्रकार की वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया। चौकी प्रभारी नरेश ननामा से इस संबंध में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि, उज्जैन शहर के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में ऑनलाइन वाहन खरीदने का झांसा देकर चोरी की घटना के मामले में दो लोगो को पुलिस ले गई है। जब पेटलावद में हुई इस प्रकार की वारदात की जानकारी होने के संबंध में चौकी प्रभारी से पूछा गया तो उनका जवाब चौकाने वाला था। चौकी प्रभारी को खुद के क्षेत्र में हुई वारदात की जानकारी नही थी। बताया जा रहा है नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में हुई वारदात में उपयोग हुए मोबाइल के आधार पर पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा है। ये लोग इस अपराध में शामिल थे या उनके मोबाइल या सिम का दुरुपयोग किया गया इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है।

साइबर क्राइम को लेकर सुस्त पुलिस

सोचने वाली बात है कि, अगर कलम सोलंकी के साथ हुई वारदात मामले में अपराध दर्ज हुआ होता या पुलिस ने आस-पास के सभी चौकी प्रभारीयों से इस प्रकार की घटना होने की चर्चा की होती तो, उज्जैन से आई पुलिस को स्थानीय स्तर पर हुई वारदात की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाती और पकड़े गए युवकों से इस वारदात की जानकारी भी जुटाई जाती। लेकिन जिले की परंपरा अनुसार थाने पर आने वाले मामलो में समझौता प्रणाली लागू होती है, जिसके चलते ज्यादातर मामलो को पुलिस समझोता प्रणाली से निपटाने में लगी है। पूर्व विदित है कि, पुलिस, चोरी जैसे संगीन अपराध को लेकर बिल्कुल भी सजक ओर मुस्तेद नही है और अपराध दर्ज नही होने की दशा में पुलिस पर अपराध को ट्रेस करने का भी दबाव नही होता है। इसी प्रकार साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के मामलों में भी पुलिस इतनी सुस्त है कि, लगभग जानकारी डेटाबेस पर उपलब्ध होने के बाद भी ऐसे अपराधियों तक पहुँचने की कोशिश नही करती, जिस कारण लगातार चोरी की घटना के साथ-साथ साइबर क्राइम की घटनाओं में वर्द्धि हो रही है। साइबर क्राइम का दर्ज ओर ट्रेस हुआ पुलिस रिकॉर्ड खंगाला जाए तो पता लगेगा कि, जिले में इस प्रकार के मामले बहुत कम है लेकिन आए दिन सामने आने वाले मामले पुलिस रिकॉर्ड के विरुद्ध है। पुलिस अपने रिकॉर्ड के दम पर विभाग में अपनी साख तो बड़ा रही है लेकिन अपराध के शिकार लोगो को सुरक्षा देने का विश्वास नही जीत पा रही हैं जो कहीं न कहीं पुलिस के प्रति गिरते विश्वास और बढ़ते अपराधों का कारण है।

मैं बालिक हो गई हूं मेरा पीछा मत करना...!

आखिर किस दिशा में जा रहा आज का युवा वर्ग ?

माही की गूंज, झाबुआ। संजय भटेवरा

विज्ञान अभिशाप है या वरदान इस विषय पर कई बार विभिन्न परीक्षाओं में निबंध पूछा गया है जिसका सार तत्व यही है कि विज्ञान का उपयोग जन हितेषी कार्यों के लिए किया जाए तो वह वरदान है यानी तर्कसंगत उपयोग वरदान है वही बिना सोचे विचारे या फिज़ूल में किया गया प्रयोग अभिशाप भी बन सकता है। विज्ञान की बदौलत थी आज पूरी दुनिया में इंसान की मुट्ठी में है और विज्ञान की वजह से ही आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है लेकिन विज्ञान ने सबसे अधिक नुकसान किया है तो वह है भारतीय संस्कृति का परंपरा का और सभ्यता का

आज पाश्चात्य संस्कृति हम पर इस कदर हावी हो चुकी है कि दीपक जलाने और कण-कण को जोड़कर लड्डू बनाने वाली हमारी परंपराओं का स्थान मोमबत्ती बुझा कर केक काटने लग गए हैं यानी यहां हमें हमारी संस्कृति जोड़ना सिखाती थी वहां अब हम बांटने में लग गए हैं। ऐसा ही विज्ञान का एक आविष्कार मोबाइल है जिसमें निसंदेह पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में हो गई है और कई मायनों में यह इंसान के लिए उपयोगी साबित हुआ है लेकिन इसका दुरुपयोग कई विपरीत परिणाम भी दे रहा है। मोबाइल की वजह से ही आज का युवा वर्ग भी भ्रमित हो रहा है जिसमें कहीं ना कहीं आज के युवा वर्ग के साथ ही पालक को की भी बराबर भूमिका है आज आए दिन हम देखते हैं कि वयस्क लड़के और लड़कियां बालक को की सहमति के बगैर ही घर से भाग कर शादी कर रहे हैं।

एक माता-पिता अपने बच्चों व उनके भविष्य के लिए कई सपने संजो कर रखते हैं और उनके सपनों को साकार करने के लिए अपने जीवन का एक पड़ाव उनके लिए अपने परिश्रम में लगा देते हैं। वही बिगड़ते इस परिवेश में कम उम्र में ही बच्चो को मोबाइल हाथों में थमा दिए जाते हैं और उस मोबाइल

का सद्उपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा कर गलत राह पर चले जा रहे हैं। वही इसी आंख-मिचोली के चलते कानूनन बालिग होकर लड़का-लड़की समझते हैं कि, हम बालिग होकर हर तरीके से मैच्योर हो गए हैं और माता-पिता एवं परिवार के संजोए सपनों को धित्तकार कर परिवार की मर्जी के विरुद्ध भागकर जीवन जीने का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि, बालिग होने के साथ मैच्योर हो जाना नहीं होता और अपनी नादानियां के साथ उठाए जाने वाले यह कदम उनकी बर्बादी का कारण एक समय के बाद अधिकांश रूप से बन जाता है।

हाल ही में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर बामनिया में मामा-बुआ के रिश्ते में आपसी संबंध बनाकर भागकर शादी कर ली, लेकिन लड़के की मां एवं परिवार ने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। वही लड़की पक्ष परिवार में रिश्ते को स्वीकार कर लिया, नतीजन एक पक्ष की ओर से ऐसे रिश्ते को सहयोग मिलने पर अपराध को भी बढ़ावा मिलता है। नतीजन लड़के ने अपने साले एवं पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही माँ को मौत के घाट उतार दिया और एक

माँ अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कुर्बान हो गई।

जब बात कानूनन से बालिग होने की है तो तय है कि, यह बालिग जब अपने माता-पिता के सपने को कूचलकर उनकी मान-मर्यादा को धूमिल करने का प्रयास कर अपने अच्छे-बुरे की समझ होने का परिचय देने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में वह दोनों अपने भविष्य की लाईफअकेले ही दोनों परिवार की ओर से किसी एक को भी सहयोग नहीं लेकर व्यापार, व्यवसाय या नौकरी कर अपना जीवन अपने लाइफपार्टनर के साथ गुजारने पर ही अपने आपको बालिक कहने वाले ये अपरिपक्व, परिपक्व की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होकर ऐसे रिश्ते में अधिकांश रूप से एक पक्ष रिश्ते को अपना लेता है लेकिन यह अपनाने वाला रिश्ता समाज-परिवार में नई पीढ़ी को गलत संदेश दे देता है और आपनाए रिश्ते का अनुसरण कर उसी परिवार की लड़की या लड़का आने वाले समय में किसी न किसी के साथ नजरे मिलाकर भागकर अपने जीवन की लाइफजीने का निर्णय ले लेते हैं।

ऐसा ही एक मामला खवासा में भी देखने को मिला जहां तीन-चार वर्षो पूर्व गांव में ही एक लड़के ने गांव के ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की लड़की को भगाकर शादी की, इतना ही नहीं लड़के-लड़की को एसपी के सुपुर्द होने के बाद लड़की अपने पिता के पास गई। उसके कुछ दिन बाद उसी लड़के के साथ भाग गई, जिसमें भी एक पक्ष परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार किया। नतीजन इस प्रकार इस परिवार की एक अपरिपक्व लड़की खवासा नटवरलाल पाटीदार, रणछोड़ पाटीदार के भाणेज परवलिया निवासी अजय पिता कैलाश पाटीदार के साथ भाग गई। इतना ही नहीं लड़की ने घर से जाते ही 10 मिनट बाद ही अपने पिता व परिवार को फोनकर कहती है कि, मैं बालिग हो गई मेने मेरे जीवनसाथी का चयन कर लिया है तुम मुझे ढूंढने का प्रयास मत करना।

यह बात एक माता-पिता व परिवार जिन्होंने अपनी बेटी के लिए कितने सपने संजोए होंगे, उन्हें एक पल में ही यह बात सुन उस माता-पिता व परिवार पर क्या गुजरती होगी यह तो वह परिवार ही उस पीड को भली-भांती समझ सकते हैं और सारी परिधी को तोड़ आर्य समाज में शादी कर लड़का अजय सोशल मीडिया पर शादी के फोटो डाल ''माय लाइफपार्टनर'' लिखकर डालता है और उक्त पोस्ट पर कोई व्यक्ति अपनी अज्ञानता का परिचय देकर बधाई देकर अपने विचार व्यक्त करता है। लेकिन ऐसे बधाईकर्ता के परिवार में जब कोई लड़की भाग जाएगी उस समय इस चीज का आभास होगा कि, ऐसे अपरिपक्वता के साथ उठाए कदम एवं शादी की बधाई देना किसी हद तक सही होता है।

जिस थाली में खाया उसी में किया छेद

वही संतोष उर्फ छोटू पिता गोपाल पाटीदार पलवाड़ा धार हाल मुकाम खवासा जिसने व्यवसायिक रूप से कई जगह अपने माता-पिता को चंपत लगाना वाला संतोष ने ऐसा कार्य किया कि, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेदकर अपनी ही मामा परिवार की लड़की को ले भागा। मामले में संतोष के मामा परिवार करवड के गंगाखेड़ी में निवासरत है और भाणेज को कुछ काम-धंधे लगाकर लाइन पर लाईन पर लाने के उद्देश्य के साथ माता-पिता के कहने पर संतोष को गंगाखेड़ी में खेती मुनाफे पर दिलवाकर मामा परिवार के घर पर ही रख कर खेती करवा रहे थे कि, 3 माह में ही अपने ही मामा परिवार जिसने भाणेज को लाईन पर लाने के लिए धंधे पर लगाया ने मामा परिवार की लड़की के साथ ही आंख-मिचोली ऐसी खेली की लड़की भी आंख-मिचोली में आ गई और अपने प्रेम को परवान चढ़ाने हेतु घर से भाग निकले।

उक्त लड़की को भगाने में संतोष का सहयोग गेल कंपनी में चौकीदारी करने वाले महेंद्र तोमर व उसके लड़के नीरज तोमर ने किया। मामले में लड़की परिवार की रिपोर्ट पर महेंद्र व नीरज दोनों को पुलिस करवड़ चौकी लेकर आई और पूछताछ की तो पुलिस के तपाने के बाद पुलिस को किसी और गए का सुराग लगने के बाद जोधपुर से लड़की-लड़के दोनों को पकड़कर ले आए। लड़की के बालिग होने में कुछ महा घट रहे थे एवं लड़की के दिए बयान पर पुलिस ने संतोष के विरुद्ध अपराध क्रमांक 438 धारा 363 में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा। ऐसी कोई घटना हो रही है जिसके हमारी भारतीय संस्कृति व माता-पिता के सपने को धुंधला कर रहे है।

प्रभारी मंत्री के दौरे के बाद हरकत में आया प्रशासन

माही की गूंज विशेषांक में उठाया था भ्रष्टाचार व अनियमित्ता का मुद्दा

माही की गूंज, झाबुआ। प्रदेश शासन द्वारा जिले में नियुक्त प्रभारी मंत्री इंदरसिंह परमार ने 17 जुलाई को जिले का प्रथम दौरा किया था। प्रभारी मंत्री के जिले में प्रथम आगमन पर माही की गूंज विशेषांक में भ्रष्टाचार, अनियमित्ताओं, बेरोजगारी सहित अन्य जनहित के मुद्दों को उठाकर प्रभारी मंत्री का ध्यानाकर्षित करने का प्रयास किया था। प्रभारी मंत्री के दौरे के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जनपद पंचायत थांदला, पेटलावद, झाबुआ व मेघनगर को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है। जिसमें 28 जून को ÷इज़ ऑफ़लिविंग÷ (जिने में आसानी) जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के लिए विभिन्न पहलों के प्रभाव का आकलन के संबंधित कार्य की प्रगति जिसमें ग्राम पंचायतों के द्वारा किए गए सर्वे कार्य उपरान्त ऑनलाईन की गई प्रविष्टी जो अत्यधिक न्यून होकर असंतोष जनक स्थिति थी। इससे स्पष्ट है कि, कार्य के प्रति उक्त जनपद पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा कोई गम्भीर प्रयास नहीं किए गए एवं कार्य में रूचि नहीं ली। उक्त जनपद पंचायतो के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के उप नियम (1), (2) एवं (3) का दोषी मानते हुए एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने व कारण बताओ सुचना पात्र जारी किया है। पर उक्त नोटिस पर क्या कार्रवाई या निराकरण होगा ये देखने के लिए महत्वपुर्ण होगा।

अज्ञात बदमाशों ने रात भर मचाया उत्पात

माही की गूंज, पारा।

बदमाशो के हौसले बुलंद होते जा रहे है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि, बदमाशो ने रविवार-सोमवार दरमियान एक ही रात में पांच दुकानों को निशाना बनाया, दुकानों के ताले तोड़ कर लाखों रुपए नगदी व सामान की चोरी की घटना को अंजाम दिया और रात भर गांव में घूमते रहे। स्थानीय पुलिस के लिए बड़ी शर्म की बात है जबकि पुलिस के पास वाहन भी है ओर रोजाना रात भर गशत भी होती है, इससे पुलिस गश्त की पोल खुलने से नकारा नहीं जा सकता है। पुलिस की निष्क्रियता से चोर सक्रिय होने लगे है, चोरी की घटना को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे मे केद हुए अज्ञात बदमाशों की तस्वीरे साफदिखाई दे रहीं है। बोरी रोड़ चौराहे पर स्थित साईं मेडिकल स्टोर्स दुकान के ताले तोड़कर चोर अंदर घुसे। दुकान मालिक अजय सिह ने जानकारी दी कि, बदमाश काउंटर के गल्ले का लॉक तोड़कर गल्ले में रखे करीब 80 हजार रूपए ले उडे, काउंटर के अंदर रखी एक फाइल के अंदर दस हजार

रूपए पड़े थे बदमाश वह भी ले भागे और दुकान का सामना गांव के बाहर फेंक गए। अजय के समीप ही गोलु राठौड़ के गोड़ाऊन के ताले भी बदमाशो ने तोड़े परंतु वहां कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसके बाद ग्राम के राम मंदिर प्रांगण में बदमाश घूमते रहे। वहीं रह रहे रहवासी ने अपना पालतू कुत्ता बदमाशो के पीछे लगा दिया तब बदमाश रफूचक्कर हो गए। वहीं पारा-झाबुआ मार्ग पर तीन स्थानों के ताले बदमाशों ने तोड़े व दो अन्य स्थानों पर चोरी करने में नाकाम रहे। इसी मार्ग पर पप्पू की किराना व पंचर की दुकान है, बदमाश पीछे की खिड़की के रास्ते से दुकान अन्दर घुसे। दुकान मालिक पप्पू ने जानकारी दी, बदमाश किराना सामान के साथ कुछ नगदी, ट्यूब, टायर करीब चालीस से पचास हजार का समान ले उड़े। पप्पू की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में आशत बदमाश चोरी करते हुए देखे जा सकते हैं। पप्पू ने बताया कि, पहले भी मेरे पर घर का ताला तोड़कर हजारों का माल चोरी हो चुका है। दोनों बड़ी घटनाओं की सूची अजय व पप्पू ने पारा पुलिस चौकी पर दी जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

13 से लेकर 18 अगस्त तक का पंचायत से लेकर तहसील का यह कैसा खेल...?

अपनी ढपली व अपना ही राग नतीजन कर रहे विवाद को उत्पन्न

माही की गूंज, खवासा।

ग्राम पंचायत का मुख्य दायित्व होता है कि, ग्राम में कोई समस्या हो तो वह समस्या को प्राथमिकता देकर उसका समाधान करवाया जाए। बात करें ग्राम पंचायत खवासा की तो यहां एक मामला ऐसा सामने आया कि, ''चोर को कहे चोरी कर साहूकार को कहे जगता रहे'' इस कहावत को भी पंचायत ने कई भागों में बांट दिया। कभी किसी को सहुकार तो कभी किसी को चोर बनाकर अपनी नाकामियों को दर्शाती है।

मामला ग्राम के दरगाह के पास से धर्मशाला मोटावड, वडली मोहल्ला, पटेल मोहल्ला आदि का गंदा पानी गहराई वाले खेतों से गुंदी वाले नाले तक के खेतों में जाता है। वहीं उक्त समस्या यहां के किसान के लिए बारिश में और ज्यादा दुविधा का कारण बन जाती है। नतीजन समस्या के समाधान के लिए एक वृद्ध किसान कनीराम पिता जगन्नाथ पाटीदार ने ग्राम पंचायत को 13 अगस्त 2020 को उक्त समस्या से निजात दिलाने हेतु आवेदन दिया कि, उक्त मार्ग पर एक तरफ नाली है जो भर जाने के बाद उनके खेत में गंदा पानी आता है अतः नाली की सफाई एवं रोड के दोनों तरफ नाली निर्माण कर समस्या से निजात दिलाई जाए। वहीं ग्राम पंचायत ने उक्त आवेदन प्रात काल आवेदनकर्ता को

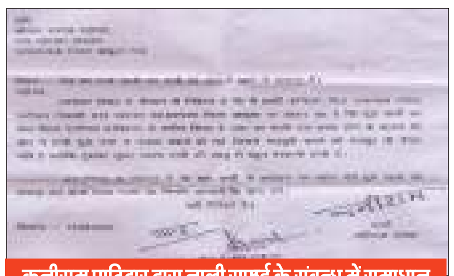

कनीराम पाटिदार द्वारा नाली सफाई के संबन्ध में समाधान हेतु पंचायत 13 अगस्त को दिया आवेदन।

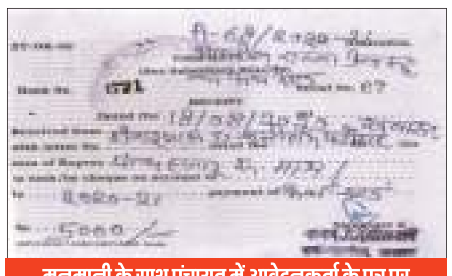

मनमानी के साथ पंचायत में आवेदनकर्ता के पुत्र पर तहसीलदार ने वसुला जुर्माना।

अपने स्तर से नाली खुदवाने को कह दिया। जिस पर आवेदनकर्ता के पुत्र शंकर पाटीदार ने जेसीबी मशीन से नाली की सफाई करवाई। लेकिन विरोधी दल को यह बात नहीं हजम होने पर ग्राम पंचायत से लेकर तहसील एवं एसडीएम कार्यालय तक शिकायत कर नाली सफाई से निकाले कचरे से रोड जाम हो गया है और उक्त नाली को शंकर पाटीदार द्वारा खोद आम रास्ता अवरूद्ध किया गया।

बिना पेन्दे की ग्राम पंचायत व तहसील कार्यालय ने अपने बेतुके निर्णय के साथ ग्राम पंचायत में पत्रक क्रमांक 258/2020 दिनांक 17 अगस्त 2020 को चौकी प्रभारी के नाम से शंकर पाटीदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के नाम से रिपोर्ट दर्ज की। जिसमें धर्मशाला के सामने मोटावड वाले शासकीय रास्ते पर हस्तक्षेप करने रिपोर्ट में दर्शाया कि, शंकरलाल डेरिया (पाटीदार) द्वारा अवैध खनन कर दिया है तथा उसमें ग्राम पंचायत का कोई सहयोग नहीं है, शंकर पाटीदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वही 18 अगस्त 2020 को टप्पा तहसील कार्यालय खवासा ने ए-68/2020-21 रसीद क्रमांक से 5 हजार रूपए का जुर्माना दिया गया। वही जुर्माने के साथ नायब तहसीलदार ने निर्देशित किया कि,

जिस नाली को शंकर से पैसे लेकर मोरम डाल नाली लेवल किया गया था, उसी को फिर पंचायत द्वारा इस वर्ष नाली सफाई की गई।

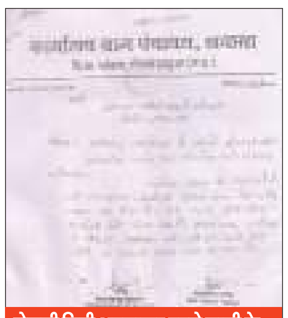

दोगली निती अपनाकर पहले नाली के संबन्ध में आवेदन प्राप्त किया और 17 अगस्त 2020 को शंकर के विरूद्ध कार्रवाई हेतु पंचायत ने दर्ज की रिपार्ट।

उक्त नाली को पुनः भरवाकर समतल किया जाए। जिस पर शंकर पाटीदार ने तहसील न्यायालय का सम्मान कर मोरम डलवाकर नाली को समतल कर दिया। इस संबंध में शंकर पाटीदार बताता है कि, मैं आ.जा.सह. संस्था का कर्मचारी हूं, जिसके लिए मुझे प्रताड़ित किया गया और विरोधी पक्ष की शिकायत पर तहसील कार्यालय व ग्राम पंचायत ने बेतूका निर्णय लेकर मेरे विरूद्ध कार्रवाई की गई। वही ग्राम पंचायत सरपंच रमेश बारिया ने वापस नाली लेवल ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया, पंचायत में दर्शाने के नाम पर मुझसे 6 हजार रूपए भी लिए थे।

आब फिर हुई सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत, तो पंचायत ने ही करवाई नाली की सफाई

पिछले वर्ष शंकर पाटीदार से आवेदन प्राप्त करने के बाद भी उक्त नाली की सफाई में ग्राम पंचायत को कोई सहयोग नहीं है, कहकर शंकर पाटीदार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली ग्राम पंचायत ने एसडीएम से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत होने पर ग्राम पंचायत में आनन-फानन में जिस मार्ग पर पिछले वर्ष शंकर पाटीदार द्वारा ग्राम पंचायत खवासा के कहने पर ही नाली की साफ करवाई थी, उसी मार्ग पर इस वर्ष ग्राम पंचायत ने नाली साफकरवाई।

हां, इस बार यह था कि, नाली सफाई करवाने हेतु शिकायतकर्ता शंकर पाटीदार नहीं होकर ग्राम के महेश नानूराम व सरवन पिता रामा पाटीदार थे। वहीं उक्त नाली की सफाई होने के बाद नाली से निकले मटेरियल की पाल बना दी। इस बार पंचायत के कार्य से समस्या का समाधान तो हुआ, लेकिन पंचायत की नाकामी यह कि, कोई सही कार्य करवाने आए और उसका विरोधी शिकायत कर दे तो ऐसे में ग्राम पंचायत से लेकर तहसील व एसडीएम कार्यालय तक के नुमाइंदे सही निर्णय लेने में क्षमता हासिल नहीं कर पाते हैं, यह दर्शा रहा हैं।

सरपंच रमेश बारिया का कहना है कि, इनके आपसी विवाद के कारण पंचायत को घसिटा जा रहा है, जो 6 हजार रूपए शंकर ने दिए थे उसका मोरम नाली भराई हेतु लगाया गया।

आखिर यह कैसा आदर्शः डमी एडमिशन करने वाली निकली आदर्श स्कूल

माही की गूंज, खवासा।

एनएचपीएस उर्फबचपन स्कूल खवासा।

कई मामलों में व्यक्ति हो या कोई संस्थान जिनके नाम के आधार पर ही उनकी व्याख्या की जाती है और व्यक्ति हो या संस्थान अपने निर्धारित नाम के साथ ही अपने कार्य को भी अंजाम देते हैं। परंतु शायद यह बात कहने और सुनने के लिए ही रह गई है। बात करें पेटलावद आदर्श स्कूल की तो, इस स्कूल का नाम भले ही आदर्श से हो पर इनके आदर्श कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। खवासा की एनएचपीएस उर्फबचपन स्कूल के डिफाल्टर संचालक की वजह से पिछले दो वर्षो से हाई एवं हाई सेकेंडरी स्कूल की मान्यता रद्द हो गई थी। देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के साथ खिलवाड़ व उनमें एक गलत संदेश स्थापित कर, दूसरे वर्ष आदर्श स्कूल पेटलावद में डमी एडमिशन कर उनके आदर्श का स्तर शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है सार्वजनिक किया। किस तरह से फर्जी एवं डमी एडमिशन दूसरे ब्लॉक के बच्चों के आदर्श स्कूल में कर शिक्षा विभाग की आपसी सांठ-गांठ के साथ कर दिए गए, जिन बच्चों को संस्था संचालको ने एक नजर से देखा भी नहीं था। इतना ही नहीं ये तय है, बच्चों के किसी भी स्कूल संस्था में न्यू एडमिशन के साथ ही बोर्ड की परीक्षा के फॉर्म भरते समय से लेकर एग्जाम तक, कहीं ना कहीं एडमिशन स्कूल संस्था में बच्चों या पालको के हस्ताक्षर होते हैं। पर आदर्श स्कूल में किस आदर्श संहिता के तहत यह हस्ताक्षर कार्य, बच्चों व पालक के स्कूल तक नहीं आने के बाद भी किस टेक्निक से करवाए होंगे, यह तो वही जाने। पर इस तरह शैक्षणिक व्यवस्था के साथ शिक्षा विभाग की कार्य व्यवस्था में पर भी प्रश्नचिन्ह जरूर लगा रहे है, जो चिंतनीय है।

अपने आदर्शो को आखिर किस दिशा में ले जा रही पेटलावद की आदर्श स्कूल।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई टाइटल कोड नंबर- एमपीएचआईएन-76422